● वर्ष-2
● अंक-222
रायपुर, मंगलवार
09 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

राजनीति में शराब घोटाले की धमक

भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से सत्तारुढ़ कांग्रेस सरकार पर ईडी और सीडी के आरोपों में फंसी होने के आरोप लगा रही है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के प्रवक्ता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा पिछले दो वर्षों से की जा रही कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बता रहे है। एक बात समझने की है कि ईडी जांच करने वाली संस्था नहीं है। सीबीआई और आयकर विभाग छापा मारकर आर्थिक एवं अन्य अपराधों की जांच करते है और इस दौरान संबंधित दस्तावेज जप्त करते है। इन जप्त दस्तावेजों में विदेशों में धन के अवैध लेन-देन की कोई बात हो तब ईडी अपना काम शुरु करता है। प्रदेश में कोयला के परिवहन में अवैध कमाई और उस कमाई की अफरा-तफरी को लेकर ईडी ने उच्च अधिकारियों, कारोबारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। अब पिछले कुछ दिनों से शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। इस सिलसिले में रायपुर नगर निगम के महापौर के भाई अनवर ढेबर को जब ईडी ने गिरफ्तार कर न्यायालय में 14 दिन की रिमांड मांगने के लिए जो आवेदन प्रस्तुत किया और उसके बाद विज्ञप्ति जारी की उससे शराब के अवैध धंधों से 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी का दावा किया गया है। ईडी ने बकायदा किस प्रकार तीन तरह से शराब के कारोबार में अवैध वसूली और कारोबार का सिंडीकेट बनाकर पैसे की लूट की गई, इसकी जानकारी विज्ञप्ति में दी गई है। इस प्रकरण के बाद राजनीति गरमा गई है। भाजपा सरकार पर हमलावर है तो सरकार 2 हजार करोड़ रुपए के घोटाले को तथ्यहीन बता रही है। वैसे तो कांग्रेस की ओर से जो तर्क दिए जा रहे है वे ज्यादा गंभीर नहीं लगते। लेकिन इस बात के कयास लगने शुरु गए है कि ईडी की कार्यवाही से जो घोटाले सामने आ रहे है उनका चुनाव पर क्या असर होगा? एक बात देखने में आती है कि चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार तब तक कोई मुद्दा नहीं बनते जब तक वह जनता के जीवन को प्रभावित न करें। इसलिए कोयला मामले में ईडी का कार्यवाही का उतना असर नहीं होगा लेकिन शराब के घोटाले को लेकर जो तथ्य सामने आए है वे चुनाव को अवश्य प्रभावित करेंगे। वह इसलिए क्योंकि मामला शराब से जुड़ा हुआ है और प्रदेश में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं की जा सकी। सरकार यह निर्णय नहीं लेने के पीछे तर्क दे रही है कि अचानक शराबबंदी से लोगों को तकलीफ हो सकती है। इधर जो तथ्य ईडी के द्वारा सामने रखे गए है उससे लगता है कि जो कमाई शराब के कारोबार से हो रही थी उसे बनाए रखने के लिए शराबबंदी का निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी ओर बिना आबकारी कर पटाए शराब के अवैध कारोबार से भी सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए गए। इससे शराब पीने वाले और शराबबंदी की मांग करने वाले दोनों पक्ष नाराज होंगे। यह नाराजगी अगले चुनाव में कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ सकती

भयानक रुप ले रहा चक्रवात मोचा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि चक्रवात मोचा का मार्ग अगले दो दिनों में साफ होने की उम्मीद है। लाल सागर बंदरगाह शहर के नाम पर यमन द्वारा चक्रवात का नाम सुझाया गया था, जिसे 500 साल पहले दुनिया में कॉफी पेश करने के लिए जाना जाता है। मौसम एजेंसी ने अपने बुलेटिन में कहा कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से सोमवार को क्षेत्र के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा इसके 9 मई के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक दबाव के रूप में तेज होने की संभावना है।कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद इसके मार्ग और गहनता का विवरण दिया जाएगा। आईएमडी ने कहा कि सिस्टम लगातार निगरानी में है और नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

रविवार को आईएमडी ने गर्मी और उमस के स्तर में वृद्धि के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी। कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरबा मेदिनीपुर, हावड़ा, पुरबा और पश्चिम बर्धमान में बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

मौसम विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, हालांकि, अगले दो दिनों में चक्रवात के कारण बारिश होने की बहुत कम संभावना है और मंगलवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अगले 24 घंटों में, उत्तरी पश्चिम बंगाल - दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में हल्की बारिश का अनुमान है।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर बंगाल के जिले चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि चक्रवाती प्रणाली

दुनिया महंगाई से परेशान, भारत बना नजीर

ब्रिटेन-यूरोप में महंगाई दर 19.1 और 17.5 प्रतिशत

नई दिल्ली। आज बढ़ती खाद्य महंगाई दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। खासकर विकसित देश भी बढ़ती महंगाई से त्रस्त दिख रहे हैं। हालांकि भारत ऐसे समय में पूरी दुनिया के लिए नजीर बना हुआ है, जहां महंगाई काबू में है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अनुसार, भारत में इस साल मार्च में महंगाई दर 4.79 प्रतिशत रही, जबकि बीती फरवरी में यह 5.95 प्रतिशत और बीते साल मार्च में 7.68 प्रतिशत थी।

दुनियाभर में हालात खराब

भारत ने जहां महंगाई को काबू कर दुनिया के सामने एक नजीर पेश की है, वहीं दुनिया के विकसित देशों समेत कई देश बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में महंगाई दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत, 19.1 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत है। वहीं लेबनान, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे में यह क्रमशः 352 प्रतिशत, 158 प्रतिशत और 102 प्रतिशत तक पहुंच गई है। कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनियाभर में महंगाई बढ़ी है।

भारत ने किया शानदार काम

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शामिका रवि ने वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े शेयर करते हुए भारत की तारीफ की। बता दें कि जिन देशों में सबसे कम महंगाई है, भारत उनमें शामिल है। रूस और यूक्रेन में दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज उगाया जाता है। दोनों देशों में युद्ध के चलते अनाज की सप्लाई दुनियाभर में प्रभावित हुई और यह महंगाई बढ़ने का कारण बनी। वहीं भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर पहले ही महंगाई को काबू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। रूस से कच्चे तेल का आयात करके भी भारत को महंगाई काबू रखने में मदद मिली। रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई को काबू में रखा।

आरबीआई ने जारी किया अनुमान

भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गया था लेकिन मार्च 2023 में यह गिरकर 5.7 प्रतिशत रह गया है। भारत में खुदरा महंगाई लगातार तीन तिमाही तक 6 प्रतिशत से ज्यादा रही थी लेकिन नवंबर 2022 में यह गिरकर 6 प्रतिशत से नीचे आ गई है। रिजर्व बैंक ने ऋण पर ब्याज दर बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग को कम रखा, जिसकी वजह से महंगाई भी कम हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरबीआई के अनुमान के मुताबिक पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रह सकती है।

आने वाले दिनों में बढ़ सकती है महंगाई

वित्त मंत्रालय का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ भी सकती है। दरअसल मई से तेल उत्पादक देश तेल उत्पादन में कटौती की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दूध और अनाज की सप्लाई में कमी के चलते भी महंगाई बढ़ सकती है। लंपी वायरस के चलते बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई, जिससे दूध की सप्लाई बाधित हुई है। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। इन वजहों से आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले विजयनगर में रोड शो के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने समर्थकों का अभिवादन किया.

ममता सरकार ने द केरला स्टोरी पर लगाया प्रतिबंध

कोलकाता। द केरला स्टोरी 5 मई को सिमेनाघरों में रिलीज हो चुकी हैं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। फिल्म ने तीन दिनों के अंदर लगभग 40 करोड़ की कमी करने वाली हैं। फिल्म को लेकर तब से विवाद है जब से इसका टीजर रिलीज हुआ था। फिल्म का दावा है कि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। इसी दावे को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को मनगढ़ंत बताया और बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को %द केरला स्टोरी% पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले की घोषणा की। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी फिल्म को कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा की। यह घोषणा ममता बनर्जी द्वारा आरोप लगाए जाने के कुछ ही मिनट बाद आई कि बीजेपी कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बंगाल पर एक फिल्म की फंडिंग कर रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फिल्म को राज्य में चल रहे स्क्रीन से हटा दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि यह निर्णय बंगाल में शांति बनाए रखने और अपराध और हिंसा से घृणा करने वाली किसी भी घटना से बचने के लिए लिया गया है।

आपको बता दे कि द केरला स्टोरी ने जनता से कड़ी प्रतिक्रिया प्राप्त की है। जहां कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, वहीं कई अन्य लोगों का मानना है कि फिल्म में प्रचार की गंध है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। अब इस पर दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी का रिएक्शन आया है। सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कॉल किए गए हैं। अदा शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म इस बारे में है कि कैसे केरल में चरमपंथी युवा महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं और उन्हें आतंकवादी समूहों का हिस्सा बनाते हैं। अब शबाना आजमी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे

अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना

बंगाल सरकार के इस फैसले का केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य फिल्म को बैन करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। वहां अभी एक मासूम बच्ची की बलात्कार और हत्या हुई, इस पर तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिल्म को बैन कर रही हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होकर उनकी सोच को बढ़ावा देने का? अनुराग ठाकुर ने रविवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग फिल्म 'द केरल स्टोरी' का विरोध कर रहे हैं, वे प्रतिबंधित पीएफआई और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के समर्थक हैं।

प्रमुख समाचार

कर्नाटक में थमा चुनावी प्रचार 10 मई को डाले जाएंगे वोट

बेंगलूरू। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले एक चरण के विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार अभियान सोमवार शाम समाप्त हो गया। यहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। वहीं, जद(एस) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कर्नाटक विधानसभा के 224 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को आएंगे। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी राज्य में 18 रैलियों को संबोधित किया और 27 अप्रैल को एक आभासी बातचीत के माध्यम से पार्टी के सदस्यों से बात की। उन्होंने छह रोड शो का भी नेतृत्व किया। इसमें बेंगलुरु में तीन और मैसूरु, कलाबुरगी और तुमकुरु में एक-एक। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाजपा के लिए प्रचार किया।

बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे

बेंगलूरू। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए लड़ रही है तो बीजेपी जीत को दोहराने में लगी है। आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। हर दल के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकता है। अगर किसी को विज्ञापन देना है तो उसे पहले एमसीएमसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। गौरतलब है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम पांच बजे थमने वाला है। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया।

मणिपुर में 2 दिन से हिंसा नहीं, कर्फ्यू में दी जा रही ढील

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र और मणिपुर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को बताया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में पिछले दो दिनों में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिमा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने मणिपुर की स्थिति पर दलीलों के एक बैच को सुना, जिसमें एक सत्तारूढ़ भाजपा विधायक द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछले बुधवार को पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा की एसआईटी जांच के लिए एक जनजातीय संगठन द्वारा मेइतेई समुदाय की स्थिति, साथ ही एक जनहित याचिका की गई।

आनंद मोहन को रिहा कर फंस गए नीतीश कुमार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या की पत्नी उमा कृष्णय्या की उस याचिका पर बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार के राजनेता आनंद मोहन सिंह की जेल से समयपूर्व रिहाई को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में उनके सहित 27 दोषियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले जेल नियमों में संशोधन के बाद सिंह की रिहाई को जेल की सजा में छूट के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी। आनंद 1994 में मुजफ्फरपुर के गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान तत्कालीन गोपालगंज कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या में कथित भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 15 साल से जेल में बंद आनंद 27 अप्रैल को जेल से बाहर आए।

झारखंड में पांच माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में पांच माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से दो माओवादियों पर कुल 15 लाख रुपये का इनाम था। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 'जोनल कमांडर' अमरजीत यादव उर्फ लखन यादव, 'सब जोनल कमांडर' शाहदेव यादव उर्फ लतन यादव, 'सब जोनल कमांडर' नीरू यादव उर्फ सालिम,'सब जोनल कमांडर' संतोष भुइयां उर्फ सुखन और सदस्य अशोक बैगा उर्फ अशोक परहिया शामिल हैं। इनमें से अमरजीत यादव पर दस लाख तथा शाहदेव यादव पर पांच लाख रुपये का इनाम था। पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) अमोल वी होमकर ने कहा, ''ये पांचों माओवादी झारखंड के चतरा, पलामू और हजारीबाग जिले तथा बिहार के गया और औरंगाबाद जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों में वांछित हैं।

दोबारा चुनाव लड़ रहे ज्यादातर विधायकों की दौलत बढ़ी

नई दिल्ली। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार सोमवार शाम थम गया। इस चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ रहे 189 विधायकों में से 168 यानी 89 फीसदी विधायकों की संपत्ति में 1 फीसदी से लेकर 1188 फीसदी तक की इजाफा हुआ है। यानी, महज 21 विधायकों की संपत्ति कम हुई है।

एडीआर और कर्नाटक इलेक्शन वॉच ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में फिर से चुनाव लड़ने वाले 189 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया। जिन 21 विधायकों की संपत्ति कम हुई है। उनकी दौलत में 0.36 फीसदी से लेकर 68 फीसदी तक की कमी आई है।

2018 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों द्वारा मैदान में उतरे इन 189 विधायकों की औसत संपत्ति 29.18 करोड़ रुपये थी। अब 2023 के चुनावों में इन 189 विधायकों की औसत संपत्ति 48.59 करोड़ रुपये हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बीच इन विधायकों की औसत संपत्ति वृद्धि 19.41 करोड़ रुपये यानी 67 फीसदी रही है।

इन पांच विधायकों की दौलत में सबसे ज्यादा इजाफा

कनकपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के डीके शिवकुमार की संपत्ति में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में उनकी संपत्ति 840.01 करोड़ रुपये थी जो 2023 में बढ़कर 1413.80 करोड़ रुपए हो गई। शांतिनगर सीट से कांग्रेस के एन.ए. हारिस की संपत्ति 2018 में 190.24 करोड़ रुपये से बढ़कर 439.20 करोड़ रुपये हो गई है।

इस सूची में तीसरे नंबर पर राजराजेश्वरनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुनिरत्न हैं। उनकी संपत्ति 2018 में 89.13 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 293.60 करोड़ रुपये हो गई। चौथा नंबर कांग्रेस के एस.एन. सुब्बारेड्डी का है। 2018 में बागेपल्ली विधायक की संपत्ति 157 करोड़ थी जो अब 313 करोड़ हो गई है। सबसे ज्यादा संपत्ति बढ़ने के मामले में हलियाल सीट से कांग्रेस के देशपांडे रघुनाथ पांचवें स्थान पर हैं। 2018 में रघुनाथ की दौलत 148 करोड़ थी जो बढ़कर 215 करोड़ रुपए हो गई है।

और अमीर हुए भाजपा विधायक

पार्टी-वार देखें तो 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के 95 विधायकों की औसत संपत्ति 20 करोड़ थी जो बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। कांग्रेस के 66 विधायकों की औसत संपत्ति 43 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ पहुंच गई। दोबारा चुनाव लड़ रहे जेडीएस के 26 विधायकों की औसत संपत्ति 2018 में 24 करोड़ थी। जो अब बढ़कर 36 करोड़ हो गई है।

बसपा के एक विधायक की संपत्ति 2018 में 20 करोड़ थी जो 2023 में बढ़कर 40 करोड़ हो गई। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक की संपत्ति पिछले चुनाव में 11 करोड़ थी जो इस चुनाव में 14 करोड़ हो गई।

इन विधायकों की दौलत घट गई

एक ओर जहां कई विधायकों की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दौलत बीते पांच वर्षों में घट गई। इस मामले में पहला स्थान गोकक सीट से भाजपा के जरकीहोली रमेश लक्ष्मणराव का है। 2018 में उनकी संपत्ति 96 करोड़ थी जो इस वक्त घटकर 49 करोड़ रह गई है।

इसके बाद होसाकोटे सीट से कांग्रेस के शरथ कुमार बचेगौड़ा का नाम है। पिछले चुनाव में उनकी दौलत 138 करोड़ थी जो अब कम होकर 107 करोड़ रुपए पर आ गई।

इस सूची में तीसरा नाम बेलगाम ग्रामीण सीट से कांग्रेस के लक्ष्मी आर. हेब्बलकर का है। पिछले चुनाव में उनकी दौलत 28 करोड़ थी जो अब घटकर 13 करोड़ रह गई है। हुनसुर सीट से कांग्रेस के एच.पी.मंजूनाथ के पास 32 करोड़ की संपत्ति थी जो अब कम होकर 22 करोड़ पर आ गई।

इस मामले में पांचवां स्थान श्रीनिवासपुर सीट से कांग्रेस के के.आर. रमेश कुमार का है। 2018 में उनकी संपत्ति 13 करोड़ थी जो इस वक्त घटकर 4 करोड़ रह गई।

भानुप्रतापपुर विधायक को ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने माँग की

नगरी। छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 3266 शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त प्राचार्य के पद पर , विगत 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जल्द से जल्द जारी करवाने शासन से पुरजोर माँग की जा रही हैं। इस कड़ी में दिनाँक 6 मई 2023 को बस्तर संभाग के कांकेर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भानूप्रतापपुर में छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह द्वारा प्राचार्य पदोन्नति मोर हक़- मोर अधिकार अभियान के तहत दिनाँक 6 मई 2023 को विधानसभा क्षेत्र भानूप्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ शासन से नये शिक्षा सत्र 16 जून 2023 के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने की माँग की गई हैं।

भेंट-मुलाकात के दौरान विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह को आश्वस्त किये हैं कि वें शीघ्र ही प्रदेश के 3266 शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूल में रिक्त प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के संबंध में मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करेंगी । विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने आश्वस्त किये हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जल्द से जल्द जारी कराने उचित पहल की जावेगी। भानूप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी से भेंट-मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने विधायक महोदया को बताया कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत टी संवर्ग में वर्ष 2013 से तथा ई संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई हैं । राज्य में तीन हजार दो सौ छियासठ शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। इन स्कूलों में प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।

प्रदेश के इन स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रहीं हैं। विगत 11 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने से टी तथा ई संवर्ग के सैकड़ों नियमित व्याख्याता तथा नियमित प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए हैं। आगामी तीन माह के भीतर अनेको व्याख्याता और प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की मृत्यु हो गई हैं।

प्रदेश के वरिष्ठ व्याख्याता तथा वरिष्ठ प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का वेतन पा रहें हैं, शासन द्वारा इन्हें प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश में 11 वर्षों से बाधित रही प्राचार्य पदोन्नति की विभागीय प्रकिया को शीघ्र पूर्ण कर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त सभी 3266 पदों पर नये शिक्षा सत्र 16 जून 2023 के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिये विधायक महोदया से त्वरित पहल करने की माँग की।

प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि, छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विगत 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिये प्राचार्य पदोन्नति मोर हक़ - मोर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई हैं, इस अभियान के अंतर्गत सभी ज़िले में मंत्रीगणों, संसदीय सचिव, विधायकगणों, निगम-आयोग-मंडलों, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों को शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जल्द से जल्द जारी करवाने समस्त नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंपने का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

धमतरी से कोंडागांव तक का रेल मार्ग

धमतरी और बस्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा : मरकाम

नगरी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने केंद्र सरकार द्वारा धमतरी से बोरई होते हुए कोंडागांव तथा जगदलपुर तक की नैरोगेज रेल मार्ग के सर्वे की अनुमति मिलने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी है। विकास मरकाम ने कहा कि यह एक बहुप्रतिक्षित मांग है जो कि क्षेत्रवासियों द्वारा निरंतर की जा रही थी। विदित हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यानी 1944 से यह रेलमार्ग बंद और मार्ग विलुप्त हो चुका था। तभी से रायपुर से बस्तर के बीच रेल्वे कनेक्टिविटी ठप थी। जो अब पुन: प्रारंभ होने जा रहा है।

विकास मरकाम ने कहा केंद्र सरकार बस्तर और आदिवासी समुदाय को विकास के धारा में गतिशील करने के निरंतर प्रयास कर रही है। रेलवे कनेक्टिविटी से बस्तर राजधानी से जुड़ जायेगा। आवाजाही, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। आदिवासी समाज को उत्थान के नए अवसर प्राप्त होंगे। विकास मरकाम ने कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बंद रेल मार्ग को प्रारंभ करने के नाम पर आदिवासियों को ठगते रहे। केंदीय बजट 2012-13 में इस लाइन को बनाने की बात करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विकास मरकाम ने धमतरी से कोंडागांव तक के रेलमार्ग बिछाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री, रेलमंत्री, भाजपा प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश माथुर और इसके लिए प्रयास करने वाले पूरे भाजपा नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया। इस मार्ग को बस्तर के लोगों का जीवन बदलने वाला बताया।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

■ भारी मात्रा में आईईडी और हथियारों सहित अन्य सामग्री बरामद

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। भेजाई थाना क्षेत्र के दंतेशपुरम जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जवान अब भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जंगल में तलाशी अभियान जारी है।

सुकमा पुलिस ने एक बयान में कहा, भेजी इलाके में नक्सलियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों के अनुसार, 8 लाख रुपये के इनामी एसओएस कमांडर मडकम एरा गोलापल्ली और 3 लाख रुपये के इनामी नक्सली नेता एरा की पत्नी पोडियम भीम को जवानों ने मार गिराया।

सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर मुठभेड़ स्थल से हथियार, भारी मात्रा में आईईडी और स्वचालित हथियारों सहित अन्य सामग्री बरामद की है, लेकिन इस पर एक आधिकारिक बयान का इंतजार है। नक्सली अरनपुर जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में थे लेकिन उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई।

इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास कच्ची सड़क पर माओवादियों ने एक शक्तिशाली आईईडी विस्फोट किया था और घायल जवानों पर गोलीबारी की थी, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के कम से कम 10 कर्मियों और उनके नागरिक चालक की मौत हो गई थी।

जब धमाका हुआ तब करीब 200 जवान एक काफिले में लौट रहे थे और पुलिस का मानना है कि 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।

पंचायत सचिव रक्तदान पश्चात रैली निकालकर भूपेश है तो भरोसा है के साथ कलेक्टर को सौपेंगे ज्ञापन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिला इकाई दुर्ग के जिलाध्यक्ष महेन्द्र कुमार साहू ने जानकारी दिया की पंचायत सचिव अपनी लंबित मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर प्रगतिरत आंदोलन को और उग्र करते हुए 8 मई को सभी जिला मुख्यालय में भूपेश है तो भरोसा है के नारा के साथ पदयात्रा रैली निकालकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर पंचायत सचिवों द्वारा अधिक से अधिक रक्तदान किया जाएगा । उसके बाद 9 मई से जिला मुख्यालय में जिला के समस्त पंचायत सचिव भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया ।विगत 16 मार्च से ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं । हड़ताल का 55 दिन पूर्ण होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा वार्तालाप नहीं करने के कारण सचिवों में रोष व्याप्त है , पंचायत सचिव के हड़ताल में चले जाने से शासन की महत्वकांक्षी योजना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, बेरोजगारी भत्ता ,फर्म ,राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ,किसान न्याय योजना ,गोबर खरीदी, रिपा कार्य, गौठान के समस्त कार्य ,मनरेगा के कार्य ,जन्म मृत्यु पंजीयन ,राशन कार्ड ,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, सामाजिक

सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धा पेंशन ,विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ,सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन ,राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना ,श्रद्धांजलि योजना, पेयजल आपूर्ति,शौचालय निर्माण ,वन अधिकार पट्टा वितरण ,स्वामित्व योजना सर्वेक्षण ,ग्राम सभा ,बजट निर्माण, समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम होने से लेखा-जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है । जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं करने के कारण एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी धरना स्थल में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया । जिलाध्यक्ष द्वारा आगे बताया गया कि शासन/प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीय करण के संबंध में कोई पहल नहीं करते हुए 24 घंटा में वापस लौटने का अल्टीमेटम जारी किया गया था ।जिसे ब्लॉक स्तरीय धरना स्थल में आदेश की प्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया ।अभी कुछ जिला के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिवों के प्रतिनिधि को बुलाकर कार्य पर वापस लौटने का दबाव बनाया जा रहा है ।जो न्यायोचित नही है ,पंचायत सचिव का प्रभार सहायक अंतरिक लेखा करारोपण अधिकारी एवं रोजगार सहायक को सौंपने का आदेश जारी किया गया है , आदेश का विरोध करते हुए सहायक आंतरिक करारोपण अधिकारी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला पंचायत सचिव के हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रभार नहीं लेने हेतु शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। एवं रोजगार सहायक संघ कोंडागांव के जिला अध्यक्ष द्वारा भी प्रभार नहीं लेते हुए सचिव संगठन के हड़ताल के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है । यदि हमारी मांगों पर शासन प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल, भूख हड़ताल ,आमरण अनशन करने के लिए संगठन बाध्य होगा।

घर के झगड़े ने भड़काई आग युवक ने बाहर खड़ी कार जलाई

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रविवार देर रात परिवार के झगड़े ने कई घरों को आग की चपेट में ला दिया। आपासी विवाद के बाद एक युवक ने घर के बाहर खड़ी स्कार्पियो गाड़ी में आग लगा दी। इसके बाद तेज लपटों के साथ धमाके हुए और आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, आरईएस कॉलोनी में रहने वाले टंडन परिवार में किसी बात को लेकर रविवार रात विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी की शोर बाहर तक आने लगा। इस पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच घर से एक युवक निकला और बाहर खड़ी स्कार्पियो कार में आग लगा दी। आग लगाते ही स्कार्पियो धू-धू कर जलने लगी। चपेट में आकर गाड़ी के टायरों में भी ब्लास्ट होने लगा। इसके बाद आग भड़क गई और आसपास के मकानों तक फैल गई।

सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक स्कार्पियो गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। उसके साथ ही मकान का लाखों रुपये का सामान भी जल गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास के घरों तक आग पहुंची, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लोगों ने पुलिस में शिकायत की है। इसके बाद मामले की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नकली नोट खपाने पहुंचा युवक गिरफ्तार, दो फरार

महासमुंद। सरायपाली पुलिस ने नकली नोट खपाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है जबकि दो आरोपित भाग निकले। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित से 25,500 रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं। थाना प्रभारी आशीष वासनिक को पांच मई की शाम मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम छिबर्रा निवासी धर्मेंद्र प्रधान(32) अपने साथी बद्री उर्फनरेंद्र पटेल एवं भागीरथी बाघ के साथ कुटेला चौक के पास स्थित एक दुकान के पास आया था। धर्मेंद्र ने 500 और 50 का नोट दिखाकर बताया कि उसके और उसके साथियों के पास काफी मात्रा में नकली नोट हैं जो असली नोट के जैसे दिखता है। धर्मेंद्र ने दुकानदार को एक प्लास्टिक के थैले में 500 और 50 के नोट का बंडल दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान व उसके साथी दुकान के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे तभी पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर सब भागने लगे। घेराबंदी कर धर्मेंद्र प्रधान को पुलिस ने धर दबोचा। उसके दो अन्य साथी भाग निकले। धर्मेंद्र प्रधान पर थाना बसना में पूर्व में भी अपराधिक कार्यों में संलिप्त होने का रिकार्ड पाया गया है।

मेकाज के डॉक्टरों ने प्रशिक्षु डीएसपी को पीटा, मामला दर्ज

जगदलपुर। जगदलपुर से 15 किमी दूर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से आगे मारेंगा चौक में बीती रात मेकाज के चिकित्सकों व पुलिस के बीच विवाद के चलते मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मेकाज के डॉक्टरों ने प्रशिक्षु डीएसपी के साथ ही उनके चालक के साथ भी मारपीट की। वहीं, परपा थाना में डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात भी सामने आई है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए परपा पुलिस ने बताया कि बीती रात प्रशिक्षु डीएसपी गर्ग अपने टीम के साथ पेट्रोलिंग में निकले थे। रात करीब एक बजे के लगभग मारेंगा चौक के पास युवक युवती को देखने के बाद पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की, इस दौरान डॉक्टर में अपने दोस्तों को फोन पर सूचना दे दिया, जिसके बाद अन्य डॉक्टर भी मौके पर आ पहुंचे, इसी बीच हुए विवाद के बाद डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षु डीएसपी के साथ ही उनके साथ आए चालक के साथ भी मारपीट की गई। जिसके चलते देर रात तक बवाल चलता रहा। घटना के बाद प्रशिक्षु डीएसपी के द्वारा मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज कराने की बात सामने आई है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को

बेमेतरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुसार 13 मई 2023 को सम्पूर्ण भारत देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जिला न्यायालय बेमेतरा में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दं.प्र.सं. तथा मेट्रोमोनियल डिस्पुट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, कब्जे के आधार पर बंटवारा, दंड प्रकिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जाना है।

कोरिया जिला मुख्यालय में कराया गया कॉम्बिंग गश्त

कोरिया। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रामगोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक जिलोक बंसल के निर्देश पर शनिवार की रात 11:00 बजे कांबिंग गश्त की गई। जिसमे शहर के कोरिया चौक, बाजारपारा, भवानी तिगड्डा, बस स्टैंड, स्कूलपारा एवं अन्य स्थानों पर पुलिस बल ने आने जाने वालों को रोककर चेकिंग की,इस दौरान कोरिया पुलिस ने हिदायत दिया कि अनावश्यक बेवजह आधी रात को शहर मे न घूमे। उक्त गश्त के दौरान बाइक, कार सहित अन्य वाहनों की जांच की गई साथ ही वाहन चालकों से पूरी डिटेल ली गई। पुलिस अधीक्षक जिलोक बंसल ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाने एवं अपराध पर नकेल कसने शनिवार कि रात कॉम्बिग गश्त किया गया है और अनावश्यक घूम रहे लोगो से पूछताछ की गई है।उक्त गश्त में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अश्वनी सिंह एवं थाना स्टाफ के साथ थाना प्रभारी अजाक उप निरीक्षक विवेक खलखो, प्रभारी रक्षित निरीक्षक रमेश पूरेना, सहायक उप निरीक्षक नैन साय बेक, बाबू लाल पैकरा, समृत मरावी सहित 40 स्टॉफगश्त में मौजूद रहे।

राईस मिल में आगजनी से लाखों का धान खाक

कवर्धा। जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र के रमतला गांव में स्थित एक राइस मिल में कल रात लगी भीषण आग से लाखों रूपए का धान जलकर राख हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि आज सुबह तक दूर-दूर तक धुंआ आसानी से देखा जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि आज तड़के रमतला ग्राम में स्थित राइस मिल से आग की लपटे देख ग्रामीण सकते में आ गए। इसी बीच मची चीख-पुकार के बाद गांव वाले राइस मिल पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। बताया जाता है कि गांव में सिद्धार्थ राइस मिल संचालित होता है। रोज की तरह कल रविवार को भी मिल के कर्मचारी काम निपटाने के बाद सोने चले गए थे। आज तड़के चौकीदार की चीख-पुकार सुनकर कर्मचारियों की नींद खुली तो पूरा मिल आग की लपटों में घिरा हुआ था। बताया जाता है कि मिल के सामने ही चौकीदार और कर्मचारियों के लिए छोटे-छोटे कमरे बने हुए हैं। चौकीदार की जब नींद खुली तो मिल आग की लपटों में घिरा हुआ था। इसके बाद यहां अफरा-तफरी मच गई।

इंटक नेताओं की राशि मामले में गबन का आरोप

■ संजीवा रेड्डी समेत चार पर मामला दर्ज

कोरबा। जिले के बालकोनगर थाना में इंटक नेताओं के खिलाफ एक और धोखाधड़ी से संबंधित एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.जी. संजीवा रेड्डी का भी नाम है। पिछले कुछ दिन से इंटक नेताओं की ग्रह दशा बदली हुई है। उनके खिलाफ लगातार शिकायतें और एफआईआर दर्ज हो रही हैं। इससे इंटक में खलबली मची हुई है। यह एफआईआर क्र. 0298 बीते 6 मई को इंटक से संबद्ध भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ के पूर्व उपमहासचिव नरेन्द्र तिवारी की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है।

इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संबद्ध यूनियन भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ के प्रबंध कार्यकरिणी अध्यक्ष जी.संजीव रेड्डी, राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ के महासचिव जयप्रकाश यादव, संघ के कोषाध्यक्ष रमेश जांगड़े को एफआईआर

में आरोपी बनाया गया है। चारों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसे पहले भी बालको थाना में संजय सिंह और जयप्रकाश यादव के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है। इस मामले में दोनों इंटक नेताओं की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नरेन्द्र तिवारी ने लिखित शिकायत में बताया है कि भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ के बैंक खाता के संचालन के लिए डॉ.जी संजीवा रेड्डी एवं संजय सिंह द्वारा जयप्रकाश यादव, रमेश जांगड़े, नरेन्द्र तिवारी को अधिकृत किया गया था। इनमें से किसी भी दो पदाधिकारी द्वारा बैंक से राशि का आहरण किया जा सकता था।

शिकायत के अनुसार नरेन्द्र तिवारी को जानकारी दिए बगैर जयप्रकाश यादव, रमेश जांगड़े द्वारा विगत छह साल से बैंक से राशि आहरित की गई। पूछे जाने पर बताया किया कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह के कहने पर आहरण किया गया है। नरेन्द्र तिवारी द्वारा राशि आहरण से संबंधित जानकारी तथा पंजीयक को प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अध्ययन किया गया। इसमें कई वित्तीय अनियमितता पाई गई। बैंक से आहरित की गई राशि और ऑडिट रिपोर्ट में भिन्नता मिली। ऑडिट रिपोर्ट भी कूटरचना कर तैयार किया जाना पाया गया। नरेन्द्र तिवारी ने अपनी शिकायत में उदाहरण दिया है कि संघ कार्यालय में नियोजित कर्मचारियों का वेतन बालको की ठेका कंपनी की ओर से प्रदान किया जाता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार संघ द्वारा यह भुगतान दिखाया गया। नरेन्द्र तिवारी ने अपनी शिकायत में और भी गड़बड़ी उजागर की है।

पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा जोन सेक्टर एवं वार्ड प्रभारियों की बैठक

दुर्ग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार पाली द्वारा जोन सेक्टर एवं वार्ड प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सोसाइटी के अध्यक्ष व विधायक अरुण वोरा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आरएन वर्मा व महापौर धीरज बाकलीवाल के विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया इस बैठक में पूर्वी ब्लाक के 3 जोन4 सेक्टर प्रभारी 11 वार्ड व 33 बूथ प्रभारियों की बैठक ली गई सभी को आगामी विधानसभा के मद्देनजर जवाबदारी दी गई अपने उद्बोधन में वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन सोसायटी के अध्यक्ष अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है आज हम छत्तीसगढ़ में जो विकास की गंगा देख रहे हैं वह भूपेश बघेल सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है सर्वहारा वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए कार्यों को हमें जन-जन तक पहुंचाना है एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार व अनीति जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में विकास अवरुद्ध हो चुका था उन्हें यह बताना भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है वह मुद्दा विहीन है क्योंकि छत्तीसगढ़ में चौमुखी विकास हो रहा है उन्होंने सभी ज़ोन सेक्टर व वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया की आप सभी अपने वार्डों में लोगों तक पहुंच कर आगामी विधानसभा को देखते हुए शासन द्वारा किए जा रहे हैं विकास कार्यों को बताएं इस बैठक में परमजीत सिंह भुर्रे,अजय मिश्रा सत्य नारायण सिंगर प्रवक्ता सुशील भारद्वाज मोहित वालदे दीपक जैन,विमल यादव ओम प्रकाश जोशी कल्याण सिंह ठाकुर अनूप पाटिल कृष्णा देवांगन छाया चौधरी मीना पॉल, एनी पीटर रवींद्र देवांगन मनीष बघेल सतीश देवांगन आनंद कपूर ताम्रकार राजेश ताम्रकार आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रद्युत देबबर्मा 10 को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे

अगरतला। टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने कहा कि वह 10 मई को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। देबबर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि शाह ने उन्हें मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच गृह मंत्रालय में विशेष सचिव ए के मिश्रा ने मणिपुर के हालात की वजह से अपने त्रिपुरा दौरे को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने मिश्रा को त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत की अगुवाई करने के वास्तेनियुक्त किया है। देबबर्मा ने रविवार को कहा, ''मिश्रा ने मुझे बताया कि वह त्रिपुरा नहीं आ रहे क्योंकि वह मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर दौरे के बाद वह दिल्ली लौटेंगे और केंद्र को वहां के हालात की जानकारी देंगे। उसके बाद वह हमारे राज्य में आएंगे।'' उन्होंने कहा, ''मिश्रा ने हमारे राज्य में नहीं आने पर अफसोस जताया। वह दो-तीन दिन में मणिपुर आ सकते हैं।

आप की छवि खराब करने भाजपा का हताशापूर्ण प्रयास

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि आबकारी नीति मामला ''आम आदमी पार्टी (आप) जैसी ईमानदार पार्टी की छवि खराब करने के लिए'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक हताशापूर्ण प्रयास है। उनकी यह टिप्पणी अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं उसे लागू करने में अनियमितता के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को शनिवार को दिल्ली की अदालत से जमानत मिलने के बाद आई है। अदालत ने कहा कि आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ साक्ष्य उन पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टयता ''साबित'' करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ''पूरा शराब घोटाला ही झूठा है। हम शुरू से यह कहते आ रहे हैं। अब तो अदालतों ने भी कहना शुरू कर दिया है।

आप के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

नईदिल्ली। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर भाजपा और आप के बीच राजनीतिक वार-पलटवार का दौर जारी है। दो आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमले कर रही है। अब भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। इतने घबराए हुए हैं कि झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 मई 2023 को एक सह-आरोपी को जमानत मिलती है और पापी आप के सारे प्रवक्ता बाहर आकर कह देते हैं कि कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया तो झाँकी हैं, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है! गौरव भाटिया ने कहा कि किसी भी अभियुक्त का बेल ऑर्डर उन्हीं के लिए होता है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि राजेश जोशी किसी मीटिंग में नहीं गए इसलिए और इन्होंने मनीष सिसोदिया को कोई पे-बैक नहीं दिया, इसलिए यह जमानत दी गई।

कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया

बेंगलुरु। जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और उनके कल्याण के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार शाम कृष्णापुरा में अपनी पार्टी के मेंगलुरु उत्तर के उम्मीदवार मोहिउद्दीन बावा के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस कट्टर हिंदू नेताओं का पार्टी में स्वागत कर रही है जबकि जद (एस) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ साठगांठ का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रीय दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं का फायदा उठा रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों के मद्देनजर बिल्वा समुदाय के वोटों को ध्यान में रखते हुए 'बिल्वा विकास निगम' गठित करने की घोषणा की है।

कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार

नयी दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''शाही परिवार'' वाले तंज के लिए सोमवार को पलटवार किया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी का जिक्र करते हुआ कहा कि देश ने उनका खून भारत के लिए बहते देखा है। सिब्बल ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री ने कहा- कांग्रेस का शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से 'अलग' हो जाए। लेकिन मोदी देश ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का खून भारत के लिए बहते हुए देखा है।'' उन्होंने कहा, ''क्या एनसीईआरटी इन तथ्यों को पाठ्य पुस्तकों से हटाने जा रही है?'' कांग्रेस नीत संप्रग के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने पिछले दिनों एक गैर-चुनावी मंच 'इंसाफ' की स्थापना की थी।

सोनिया गांधी के बयान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पलटवार, कहा-

ये कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन का नतीजा है

बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वार-पलटवार का दौर जारी है। सोनिया गांधी को लेकर भाजपा जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो संप्रभुता की बात कही है ये कांग्रेस पार्टी के सोच के मानसिक दिवालियापन का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वोट के खातिर कुछ भी बोलना और कुछ भी कहना ये बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है। नड्डा ने कहा कि वो भी सांसद रही हैं और अभी भी हैं और खरगे साहब भी रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करे तो कर्नाटक के हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी...ये उनका अपमान है लेकिन ये लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के शब्द उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी पर बोलते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय

अध्यक्ष ने कहा कि वह राजनीतिक पर्यटन के लिए (राज्यों) का दौरा करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो वे जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम साल भर चौबीसों घंटे लोगों के बीच रहते हैं। यही भाजपा और कांग्रेस नेता के बीच का अंतर है।

कर्नाटक कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध का उल्लेख करने पर विवाद के बीच, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने खुद प्रतिबंध का उल्लेख किया। नड्डा ने कहा कि जब उन्होंने कहा, तो लोगों ने उन्हें परिणाम दिखाया। अगर आप किसी को खुश करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तय कर लेते हैं कि सामने वाले को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है। सभी क्षेत्रों में भाजपा के प्रति रूझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बड़ा है..भाजपा वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

सोनिया गांधी के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा

भाजपा ने सोमवार को निर्वाचन आयोग का रुख कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने और चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा की ओर से कहा गया, कर्नाटक भारत संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है और यह खतरनाक और घातक परिणामों से भरा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्होंने (सोनिया गांधी) जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का घोषणापत्र टुकड़े-टुकड़े गैंग का एजेंडा है और इसलिए वे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस देश विरोधी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी नेता तरुण चुघ ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए।

कर्नाटक की संप्रभुता का जिक्र करने से कांग्रेस की भारत को तोड़ने की गहरी साजिश का खुलासा हुआः अनुराग

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा कथित तौर पर कर्नाटक की संप्रभुता का जिक्र करने से पार्टी की भारत को तोड़ने की गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। ठाकुर ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की संप्रभुता का हवाला देकर सोनिया गांधी आपने भारत को तोड़ने की कांग्रेस की गहरी साजिश का खुलासा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि लोग यह नहीं भूले हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार ने जनभावना के खिलाफ जाकर शरारतपूर्ण ढंग से भाजपा की एक राष्ट्र, एक ध्वज के प्रति निष्ठा का उपहास उड़ाने के लिए कर्नाटक के लिए एक अलग झंडा पेश किया था। ठाकुर जाहिर तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कदम का जिक्र कर रहे थे, जब उसने कर्नाटक के लिए राज्य के झंडे के लिए एक नए डिजाइन को मंजूरी दी थी और केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था। फिल्म केरल स्टोरी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब खुद सत्ता में थे तब कुछ और कहते थे और अब इसे झूठ और प्रोपेगेंडा बता रहे हैं।

कर्नाटक में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी सरकार, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की : शाह

बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव को लेकर सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में मेरा दौरा हुआ है। सभी क्षेत्रों में भाजपा के प्रति रूझान, उत्साह और समर्थन गत चुनाव की सापेक्ष में बहुत बड़ा है..भाजपा वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि 4ब मुसलिम आरक्षण हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है क्योंकि वो गैर-संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत ये मुस्लिम आरक्षण किया था, जिसको हमने हटा दिया है। इससे पहले शाह ने कहा था कि मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि कर्नाटक का चुनाव बजरंग बली पर चला गया है तो मैंने कहा कि बजरंगी बली तो अपने मंदिर में ही थे, ये कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति... जिसके कारण इन्होंने सालों तक प्रभु श्रीराम को ताले के अंदर बंद करके रखा और आज बजरंग बली को बदनाम करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लिए, कर्नाटक एक एटीएम है।

नीतीश कुमार से जल्द ही मुलाकात करेंगे एनसीपी अध्यक्ष

पवार आम चुनाव में भाजपा को हराने विपक्षी एकता का हिस्सा बनेंगे

कर्नाटक। कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारी में हैं। सभी एक दूसरे को हराने की रणनीति में लगे हुए है। कोई किसी पार्टी से सांठगाठ कर रहा तो कोई किसी नेता से। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों नेता आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं। हालांकि अब शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जल्द ही नीतीश से मुलाकात करेंगे।

गत शुक्रवार को राकांपा प्रमुख के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले को वापस लेने वाले पवार कर्नाटक के निपानी जाने से पहले सोलापुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पवार पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक रैली में भाग लेंगे।

जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संभावित मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि मुझे संदेश मिला है कि नीतीश 11 मई को मुंबई आएंगे। हम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमारा मानना यह है कि देश में (भाजपा सरकार के) एक विकल्प की जरूरत है।

राकांपा प्रमुख ने सभी पार्टियों को एक साथ होने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं, वे दे सकते हैं। चाहे वह नीतीश हों या ममता (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता) मेरे विचार से हम सभी को इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में उनके राजनीतिक सहयोगियों शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के साथ लोकसभा सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। राकांपा, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस तीनों ही दल महा विकास आघाड़ी गठबंधन के घटक हैं। उन्होंने कहा कि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता एक साथ बैठेंगे और फिर सीट बंटवारे के विषय पर चर्चा करेंगे। इस तरह की बैठकों से पहले किसी विशेष लोकसभा सीट पर दावा करने का कोई मतलब नहीं है। बता दें, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं।

शिवसेना के मुखपत्र में एनसीपी सुप्रीम पर तंज

मुंबई। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) के पार्टी के मुखपत्र सामना ने सोमवार को पार्टी के प्रमुख सहयोगी शरद पवार की आलोचना करते हुए कहा कि एनसीपी अध्यक्ष एक उत्तराधिकारी तैयार करने में विफल रहे जो पार्टी को आगे ले जा सके। हालांकि, अखबार ने पवार को इस बात के लिए भी श्रेय दिया कि उन्होंने अपने इस्तीफे के प्रकरण के साथ एनसीपी को विभाजित करने की भाजपा की योजना को नाकाम करने के लिए एक मास्टरस्ट्रोक स्टेप लिया। शरद पवार राजनीतिक क्षेत्र के एक पुराने पेड़ की तरह हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, जिससे उनकी उपस्थिति का अहसास हुआ। हालांकि, वह ऐसा नेतृत्व तैयार करने में नाकाम रहे हैं, जो उनके बाद पार्टी की बागडोर संभाले। पार्टी की जड़ें महाराष्ट्र में हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

मुंबई और बैंगलोर को प्लेऑफ में जगह बनाने की जंग कड़ी

मुंबई। अब जबकि प्लेऑफ में जगह बनाने की जंग कड़ी हो गई है तब मुंबई इंडियंस के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म और डेथ ओवरों की गेंदबाजी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। रोहित ने अभी तक 10 मैचों में 18.39 की औसत से 184 रन बनाए हैं। यह लगातार दूसरा सत्र है जबकि उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है। मुंबई अभी अंक तालिका में छठे स्थान पर है और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसके प्रमुख बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

इस आईपीएल में रोहित की भूमिका शीर्ष क्रम में टीम को तेज शुरुआत देना है। वह कुछ मैचों में ऐसा करने में सफल रहे लेकिन अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाए। उनके जल्दी आउट हो जाने से टीम के मध्यक्रम पर दबाव पड़ रहा है। पिछले साल आईपीएल में भी रोहित अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने तब 14 मैचों में 268 रन बनाए थे और उनकी टीम अंतिम स्थान पर रही थी। मुंबई के लिए यह अच्छी बात है शीर्ष क्रम में रोहित के नहीं चलने पर उसके पास ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी हैं जो बखूबी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

रोहित पर से दबाव हटाने के लिए मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा लेकिन उसका यह दांव भी नहीं चल पाया। रोहित लगातार दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए जबकि उनकी जगह पारी का आगाज करने वाले ग्रीन केवल छह रन ही बना सके। मुंबई इस मैच में आठ विकेट पर 139 रन ही बना पाया और उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रोहित की फॉर्म के अलावा मुंबई के लिए डेथ ओवरों की गेंदबाजी भी चिंता का विषय बनी हुई है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 710 अंक चढ़ा निफ्टी 18,250 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 710 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में 195 अंको की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,264 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 709.96 अंक यानी 1.16 फीसदी मजबूत होकर 61,764.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 61,854.19 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 61,166.09 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 195.40 अंक यानी 1.08 फीसदी की तेजी देखी गई। निफ्टी कारोबार के अंत में 18,264.40 अंक पर बंद हुआ।

भारत का कोल आयात 22-23 में बढ़कर 16.2 करोड़ टन हुआ

नयी दिल्ली। भारत का कोयला आयात वित्त वर्ष 2022-23 में 30 प्रतिशत बढ़कर 16.24 करोड़ टन हो गया। यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष में 12.5 करोड़ टन था। एमजंक्शन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि कोकिंग कोल का आयात 2022-23 में 5.44 प्रतिशत बढ़कर 5.44 करोड़ टन हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 5.16 करोड़ टन था। मार्च 2023 में गैर-कोकिंग कोयले का आयात 1.38 करोड़ टन रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 1.26 करोड़ टन था। मार्च 2023 में कोकिंग कोल का आयात 39.6 लाख टन रहा, जो मार्च 2022 में 47.6 लाख टन था। भारत दुनिया के शीर्ष पांच कोयला उत्पादक देशों में शामिल है। हालांकि, उसे कोयले की आवश्यकता के कुछ हिस्से को आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। देश कोकिंग कोल के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्पात बनाने में होता है।

भारत, कनाडा के व्यापार मंत्री मुक्त व्यापार समझौते पर जारी बातचीत की समीक्षा करेंगे

नयी दिल्ली। भारत और कनाडा के व्यापार मंत्री दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर जारी बातचीत की प्रगति की समीक्षा करेंगे। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि इस दौरान दोनों नेता आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा करेंगे। बयान के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा की उनकी समकक्ष मैरी एनजी सोमवार को ओटावा में छठी भारत-कनाडा मंत्रिस्तरीय वार्ता (एमडीटीआई) के लिए चर्चा की सह-अध्यक्षता करेंगी। एमडीटीआई एक द्विपक्षीय तंत्र है, जो व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों और सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा के लिए संस्थागत व्यवस्था मुहैया कराता है। बयान के मुताबिक चर्चा द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने, हरित रूपांतरण सहित विभिन्न विषयों पर केंद्रित होगी।

अमेरिका-यूरोप बढ़ती महंगाई से परेशान, भारत बना नजीर

नई दिल्ली। आज बढ़ती खाद्य महंगाई दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। खासकर विकसित देश भी बढ़ती महंगाई से त्रस्त दिख रहे हैं। हालांकि भारत ऐसे समय में पूरी दुनिया के लिए नजीर बना हुआ है, जहां महंगाई काबू में है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अनुसार, भारत में इस साल मार्च में महंगाई दर 4.79 प्रतिशत रही, जबकि बीती फरवरी में यह 5.95 प्रतिशत और बीते साल मार्च में 7.68 प्रतिशत थी। भारत ने जहां महंगाई को काबू कर दुनिया के सामने एक नजीर पेश की है, वहीं दुनिया के विकसित देशों समेत कई देश बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में महंगाई दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत, 19.1 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत है। वहीं लेबनान, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे में यह क्रमशः 352 प्रतिशत, 158 प्रतिशत और 102 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस : एक बहुमूल्य रत्न!

पीयूष गोयल

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। इसके माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समितियों ने किसी एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख ऑनलाइन लेनदेन के जरिए दो लाख करोड़ रुपये (24 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की। यह समावेशी विकास, पारदर्शिता, दक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वचनबद्धता का एक उत्कृष्ट प्रमाण है।

जीईएम सही अर्थों में एक रत्न है। इसने पुराने पड़ चुके आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) का स्थान लिया है। उचित रूप से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय भवन, वाणिज्य भवन, का निर्माण उस भूमि पर किया गया है जहां कभी डीजीएसएंडडी हुआ करता था। इस भवन के शिलान्यास समारोह में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सही ही कहा था- अब 100 साल से अधिक पुराने इस संगठन को बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर डिजिटल तकनीक पर आधारित एक नए निकाय - गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस ङ्क को लाया गया है। जीईएम ने सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के तौर-तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है।

अगस्त 2016 में स्थापित होने के बाद से, जीईएम के कामकाज में असाधारण प्रगति हुई है। इस पोर्टल पर होने वाले लेनदेन का कुल मूल्य 2022-23 में लगभग दोगुना होकर पिछले वित्तीय वर्ष में 1.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 422 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ इसकी अनूठी यात्रा शुरू हुई थी। इस पोर्टल का शुभारंभ वस्तुओं एवं सेवाओं की सार्वजनिक खरीद को प्रधानमंत्री के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के मिशन और सरकारी प्रणालियों को ईमानदार, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की उनकी रणनीति के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से किया गया था। जीईएम की प्रतिस्पर्धी बोली जैसी पारदर्शी कार्यप्रणालियों ने सरकारी विभागों एवं उपक्रमों को करदाताओं के लगभग 40,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद की है। इस तरह की पहलों ने मोदी सरकार को राजकोषीय स्थिति से समझौता किए बिना कल्याणकारी कार्यों पर होने वाले व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करने में मदद की है। कई अर्थों में, जीईएम लोगों द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पक्ष में जबरदस्त मतदान किए जाने के बाद से शासन-प्रशासन में लाए गए बदलावों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। लोग पिछली सरकार से तंग आ चुके थे, जो हमेशा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहती थी। उस सरकार के कई मंत्रियों के लिए तो विभिन्न अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर छपने वाली शर्म और लांछन की रोज की खुराक ही उनकी जीवनशैली का एक आधार थी। इस संदर्भ में, जीईएम का महत्व वित्तीय दृष्टि से इसकी अभूतपूर्व वृद्धि से कहीं अधिक है और यह अपने-आप में ई-कॉमर्स की किसी भी बड़ी कंपनी को ईर्ष्या से भर देने के लिए काफी है। इस नई प्रणाली ने सदियों पुरानी उन प्रक्रियाओं की जगह ली है जो अक्षमताओं और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थीं। सरकारी खरीद अपारदर्शी, काफी समय लेने वाली, बोझिल और भ्रष्टाचार एवं निर्माताओं की गुटबंदी (कार्टेलाइजेशन) में लिप्त हुआ करती थी। केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही प्रवेश संबंधी विशाल बाधाओं को पार कर पाते थे। खरीदारों के पास विशेषाधिकार प्राप्त और अक्सर बेईमान आपूर्तिकर्ताओं से ऊंची एवं बिना मोल-भाव वाली कीमतों पर घटिया सामान खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जबकि संभावित विक्रेताओं को सूचीबद्ध होने और फिर समय पर भुगतान पाने के लिए पूरी तरह से सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी की दया पर निर्भर रहना होता था और दर-दर भटकना पड़ता था।

क्रमशः ...

आतंकवाद के घिनौने स्वरूप को उजागर करती द केरला स्टोरी

सनी राजपूत

भारत में आतंकवाद के जिस स्वरूप को केवल एक कथानक मानकर स्वीकार करने से परहेज किया जाता रहा है। आतंकवाद के उस घिनोने स्वरूप की कलई खोलती है, द केरला स्टोरी। जहां प्रेम करना भी हराम हो, वहां जिहाद के लिए लव करना हलाल हो जाता है। द केरला स्टोरी को कहानी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह तो उस सत्य घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके माध्यम से भारत की हजारों हिंदू सहित सभी गैर इस्लामिक लड़कियों को इस्लामिक देशों में बैठे आतंकवादीयों की शारिरिक भूख की पूर्ती के लिए एक वस्तु बनाकर उनके सामने फेंक दिया गया। यदि बात की जाए फिल्म की तो फिल्म में तीन कहानियां एक साथ आगे बढ़ रही है। एक कहानी में अमेरिकी सेना ने एक महिला आतंकवादी को हिरासत में ले रखा है। यह फिल्म का वर्तमान है। और दो कहानियां फ्लैशबैक में चल रही है। एक कहानी सामान्य जीवन की है और एक है लव जिहाद के षड्यंत्र की कहानी। फिल्म में बहुत अच्छी तरह से चार लड़कियों को दिखाया गया है, जो कि चार वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही है। पहली एक मूल हिंदू परिवार से है। जिसका परिवार हिंदू संस्कृति और परम्पराओं का निर्वहन कर रहा है किन्तु नयी युवा पीढ़ी को उन परम्पराओं और रीति रिवाजों से कुछ विशेष लगाव नहीं है। दूसरी लड़की एक कम्युनिस्ट परिवार से है जो भगवान, संस्कृति और परम्पराओं को नहीं मानती है। तीसरी लड़की एक कैथोलिक ईसाई है, जो अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का अनुसरण करती हैं। और अंत मे है एक मुस्लिम लड़की जो अपने मजहब के अनुसार जिहाद के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। फिल्म में चारों लड़कीयां नर्सिंग की पढाई के लिए अपने घर से दूर एक कॉलेज में आती है। और वहां होस्टल में ही रहती है। चार में से तीन लड़कीयां वास्तविक रूप से पढ़ने ही आयी है। लेकिन आसिफा मजहब का अनुसरण करते हुए जिहाद के लिए भी काम कर रही है। आसिफा बार-बार बाकी तीनों से बातचीत करते हुए एक ही बात कहती है। जिसे हम सामान्य जीवन में दिन में पांच बार रोजाना सुनते है कि केवल एक ही ईश्वर है। यही बात आसिफा भी बार बार दोहराती है। आसिफा कॉलेज के पास ही रहती है और हमेशा अपने घर वालों के संपर्क में रहती है। और अपने मजहबी रीति रिवाजों का पूरा अनुसरण करती है। ईद पर अपने घर जाती है। अपनी तीनों मित्रों को साथ ले जाती है। और फिर कुछ ऐसा घटता है कि आसिफा बाकी तीनों लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए भी तैयार कर लेती है। आसिफा जहां अपने मजहबी त्यौहार पर घर जाती है। वहीं बाकी दो हिंदू लड़कियां दीपावली पर भी घर ना जाते हुए त्यौहार पर होने वाली परेशानियों की बाते करने लगती है। और कहती है भक्ति करने के लिए बुढापे का समय पड़ा है। समय के साथ आसिफा अपने षड्यंत्र में सफल होती है और अपने मजहबी मित्रों के साथ लव जिहाद को अंजाम देती है। और उन तीनों गैर इस्लामिक लड़कियों के साथ वही होता है जो हम वर्तमान में अपने आस-पास देख रहें हैं। अब प्रश्न यह आता है कि लव जिहाद के विषय में हमारें आसपास जो भी लव जिहाद से जुड़ी घटनाएं देख रहें है या फिल्म में भी जो दिखाया गया है। उसके बाद भी गैर इस्लामिक लड़कियां ऐसे घिनौने षड्यंत्र का शिकार कैसे बन रही है। तो फिल्म के एक दृश्य में बताया जाता है कि तीन में से दो लड़कियां हिजाब पहनकर ही छुट्टियों में अपने घर भी जाती है। और हिंदू लड़की को उसकी मां प्रसाद देती हैं। तो लड़की का जवाब होता ऐसे भगवान किस काम के है जो स्वयं की भी रक्षा ना कर सकें। तो मां की ओर से जवाब में एक थप्पड़ पड़ता है। यह एक थप्पड़ हिंदू परिवार की लाचारी को प्रदर्शित करता है। हिंदू परिवार में युवा पीढ़ी को उनके धार्मिक-संस्कृति रीति रिवाज और कथाओं से कभी परिचित ही नहीं करवाया जाता है। केवल आधुनिक शिक्षा के नाम पर स्कूलों में डाल दिया जाता हैं और वहां पढ़ाकर नौकरी के लिए तैयार किया जाता है।

शरद पवार : राजनीति के 'नटसम्राट'

अजय बोकिल

महाराष्ट्र की राजनीति में दिग्गज नेता शरद पवार के इस्तीफे और तीन दिन बाद उसे वापस लेने के प्रहसन के बाद किसी ने मराठी में कटाक्ष करते हुए पवार को भारतीय राजनीति का 'नटसम्राट' कहा। खास बात यह थी कि इस तीन दिनी प्रहसन की पटकथा भी शरद पवार ने ही लिखी थी और वो ही इस एपीसोड के निर्देशक, हीरो भी थे। ऐसा हीरो जिसने पटकथा के विलेन को बिना वार के ही रिंग से बाहर कर दिया।

इस पटकथा का आरंभ भी पवार ने किया था और अंत भी उन्होंने किया। यह अलग बात है कि यह अंत उनके महत्वाकांक्षी भतीजे अजित पवार के लिए 'शोकांतिका' की तरह रहा। एक और अहम बात यह रही कि पवार ने भारतीय राजनीति को कुछ नए मुहावरे दिए, जो लंबे समय तक चलेंगे।

शरद पवार, उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनकी विचारधारा क्या है? इन सवालों का एक ही जवाब है अवसरवादी राष्ट्रवाद। पवार और उनकी पार्टी की कभी किसी से दुश्मनी नहीं रही और दोस्ती उन्होंने अपने लाभों के हिसाब से की। वो कब कहां, किस पाले में, किन तर्कों के आधार पर चले जाएंगे या हट जाएंगे, यह केवल पवार ही जानते हैं। वर्तमान में उन्हें भाजपा से दूरी बनाए रखने और विपक्षी खेमे में बने रहने में ज्यादा लाभ दिख रहा है। बल्कि यह कहें कि भाजपा जैसी सहयोगियों को 'खा जाने वाली' पार्टी से वो अपने दल को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। यही उन्होंने किया भी।

शरद पवार आज शायद देश के उन सबसे बुजुर्ग नेताओं में से हैं, जो सियासत में 63 साल से न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि अपना महत्व बनाए हुए हैं। खुद को दिग्गज राजनेता यशंवत राव चह्वाण का शिष्य मानने वाले पवार राजनीति के धुरंधर और पूर्वानुमान लगा लेने वाले खिलाड़ी हैं। छह दशकों की सक्रिय राजनीति और सियासत के कई उतार-चढ़ाव देख चुकने के बाद आत्मकथा तो बनती ही है। लेकिन अपनी आत्म कथा 'लोक माझे सांगाती' (लोग मेरे साथी) के विमोचन अवसर को भी उन्होंने राजनीतिक विस्फोट का प्लेटफार्म बनाया।

पवार ने राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की घोषणा करके राजनीति में भूचाल ला दिया। इसके पहले उन्होंने मुहावरेदार अंदाज में कहा था कि 'अब 'रोटी पलटने' का वक्त आ गया है। समय पर रोटी न पलटी जाए तो जल जाने का खतरा रहता है।' तब लोग इस मुहावरे के निहितार्थ भांपने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पवार के इस्तीफे ने साफ कर दिया कि उन्होंने तुरूप का

इक्का चल दिया है।

पवार की इस अप्रत्याशित घोषणा के बाद उनकी पार्टी में मानो हाहाकार मच गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मानों चाटुकारिता की होड़-सी लग गई। पवार का इस्तीफा मानो पार्टीजनों के जीवन-मरण का प्रश्न बन गया। सभी यह दिखाने में लगे थे जैसे पवार कभी रिटायर हो ही नहीं सकते। इसमें लाचारी का भाव भी था।

यह दृश्य देखकर 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेसनीत यूपीए की जीत के बाद यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद स्वीकारने से इंकार करने पर जिस तरह कांग्रेसियों ने प्रलाप किया और उन्हें मनाने के लिए क्या नहीं किया, उसकी याद आ गई। वो पीएम न बनी तो कयामत आ जाएगी। लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच चारित्रिक फर्क है।

सोनिया कार्यकर्ताओं के रोने पीटने से पिघलने की बजाए अपने फैसले पर आखिर तक अड़ी रहीं जबकि पवार के इस्तीफे का नाटक उस हेलीकॉप्टर शॉट की तरह था, जिसमें बल्लेबाज को यकीन रहता है कि गेंद बाउंड्रीपार जानी ही है। वो गई भी। तीन दिन तक 'पुनर्विचार' बाद पवार ने यह कहकर इस्तीफा विवशभाव से वापस ले लिया कि क्या करूं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनादर नहीं कर सकता।

इस 'अंत' का अंदाजा हर उस व्यक्ति को था, जो पवार की राजनीति को बारीकी से जानता-समझता है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब पवार के नेतृत्व को उनकी पार्टी में कोई चुनौती नहीं थी तो इस्तीफे के प्रहसन के मंचन की जरूरत क्या थी? अमूमन किसी भी पार्टी में शीर्ष नेताओं के इस्तीफे अथवा रिटायरमेंट की एक प्रक्रिया होती है। यह काम सुविचारित और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसे पार्टी के कर्णधारों का समर्थन होता है। मसलन भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी की जगह नरेन्द्र मोदी को प्रोजेक्ट करने फैसला हुआ तो छुटपुट विरोध को छोड़ उस पर व्यापक सहमति थी।

समाजवादी पार्टी में खुद मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को और लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव को उत्तराधिकार सौंप दिया। कहीं कोई आवाज नहीं उठी। पवार भी ऐसा कर सकते थे। वो पार्टी को विश्वास में लेकर बेटी सुप्रिया सुले अथवा अजित पवार में से किसी एक को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर सकते थे या कोई दूसरा संतुलन साध सकते थे।

लेकिन उन्होंने खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर उसे वापस लेने की बाजीगरी दिखाई। इसे उन्होंने फिर एक नए मुहावरे में व्यक्त किया कि मैंने 'रोटी बेल दी' (मराठी में भाकरी थापली) है। यानी अब उसके खराब होने का खतरा टल गया है। पवार के ये मुहावरे भारतीय राजनीति में आगे भी प्रयुक्त होते रहेंगे।

इस पूरे प्रहसन से हासिल क्या हुआ? इसके बारे में राजनीतिक प्रेक्षकों का अलग-अलग आकलन है। पहला तो यह कि उन्होंने अपनी राजनीतिक गद्दी की दावेदारी से भतीजे अजित पवार को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है। अजित दादा के बारे में यह अफवाहें तैर रही थीं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं और बड़ी संख्या में राकांपा विधायकों को लेकर भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। अजित अभी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन उन्हें विपक्ष में रहना रास नहीं आ रहा है।

शिवसेना से उनकी ज्यादा बनती नहीं है। तीन साल पहले भी वो तड़के अल्पजीवी देवेन्द्र फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे और बाद में 'काकासाहब' की मार्मिक गुहार के बाद इस्तीफा देकर पार्टी में लौट आए थे। लेकिन वो मजबूरी थी। सियासी अरमानों का पैमाना वैसा ही छलक रहा था। अजित कितने भी 'गुड़' हों, सियासी चालों के मामले में काकासाहब 'शक्कर' हैं।

पवार ने खुद इस्तीफे का दांव चलकर पार्टी की जबर्दस्त सहानुभूति बटोरी, अपनी अपरिहार्यता दिखाई और अजित के अरमानों पर फिलहाल तो पानी फेर दिया है। यह तब साफ झलका, जब पवार द्वारा इस्तीफा वापस लेने की घोषणा के दौरान जुटे दरबार में अजित नदारद थे। मीडिया ने पूछा तो पवार ने उड़ता-सा जवाब दिया कि मैंने किसी को नहीं बुलाया। उल्टे उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि क्या पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार आते हैं?

इशारा साफ था कि अजित दादा का उनकी निगाह में अब कोई मोल नहीं रह गया है। वो पार्टी में रहें, चाहें जाएं। अलबत्ता इस्तीफा वापसी के दूसरे दिन अज्ञातवासी अजित का एक बयान जारी हुआ कि पवार साहब के इस्तीफा वापस लेने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। हालांकि इस इस्तीफा प्रहसन का क्लायमेक्स इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि पवार चाहकर भी बेटी सुप्रिया को अपना अधिकृत उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सके। इसके लिए शायद उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि वो कोई नई रोटी बनाएं।

दूसरा पहलू, इस्तीफे के माध्यम से पवार का पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ का इजहार था, जिसका संदेश सभी विपक्षी पार्टियों में गया है। साथ में यह संकेत भी कि महाराष्ट्र का यह शेर अभी जिंदा है और आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यह परोक्ष हुंकार उस मुहिम को चुनौती देने की लिए थी, जिसके तहत नीतीश कुमार को विपक्षी मोर्चे के संभावित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की अघोषित कोशिश की जा रही है।

बहरहाल न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में इस इस्तीफा प्रहसन की गूंज देखने को मिलेगी। वो इस रूप में कि क्या महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाडी कायम रहेगी या नहीं और क्या राष्ट्रीय स्तर एक विपक्ष अभियान अगले लोकसभा चुनाव तक साकार होता है या नहीं। और यह भी कि भारतीय राजनीति का यह 'नटसम्राट' अब किस भूमिका में होगा?

भारतीय ज्ञान परंपरा....

संंन्यासोपनिषद् (भाग-3)

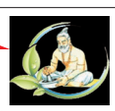

गतांक से आगे...

नपुंसक, पतित, अङ्गहीन, स्त्रैण (नारी स्वभाव वाला), बधिर, बालक, वाचाल, पाखण्डी, चक्री (चक्र चिह्न से अंकित अपराधी या कुचक्र रचने वाला), कुष्ठी, वैखानस एवं ब्राह्मण पद से भ्रष्ट, वेतनभोगी अध्यापक, अजितेन्द्रिय, अग्निहोत्र से रहित, नास्तिक विरक्त होते हुए भी संन्यास दीक्षा के उपयुक्त नहीं होते। यदि कहीं वे संन्यासी हो भी जाएँ, तब भी वे महावाक्य के उपदेश में पूर्ण सक्षम अधिकारी नहीं होते।

पतित की सन्तान, निकृष्ट नख से युक्त, मैले दुर्गन्धयुक्त दाँत वाले, क्षयरोग ग्रस्त, विकलांग आदि संन्यास धर्म की दीक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होते। जिन्हें अकस्मात् वैराग्य हो गया हो, महापातकी, व्रात्य (संस्कारहीन) एवं लोक में निंदित व्यक्तियों को संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। जो (मनुष्य) व्रत, यज्ञ, तप, दान, होम और स्वाध्याय-रहित हैं, सत्य एवं शुचिता से विहीन हैं, उन्हें संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। इस तरह के लोग चाहें तो आतुर संन्यासी हो सकते हैं; किन्तु ऐसे लोग संन्यास के नियमानुसार अधिकारी नहीं हो सकते।

भूः स्वाहा मन्त्र पढ़कर शिखा (चोटी) को दूर कर दे अर्थात् काट दे; किन्तु यज्ञोपवीत को रहने दे। हे यज्ञ ! (आप हमें) बल, ज्ञान, वैराग्य एवं मेधा को प्रदान करें, इस प्रकार कहकर यज्ञोपवीत को छिन्न- भिन्न कर दे। भूः स्वाहा मंत्र पढ़कर वस्त्र एवं कटि-सूत्र को जलाशय में विसर्जित करके संन्यस्तं मया (मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया), इस मंत्र का उच्चारण तीन बार करना चाहिए। संन्यासी एवं द्विज को देखकर भास्कर अपने स्थल से चलायमान होने लगता है कि कहीं यह हमारे मण्डल को भेद करके परब्रह्म में न समा जाए।

जो ज्ञानी मनुष्य मैं संन्यासी हो गया ऐसा स्वीकार वचन बोलता है, वह अपने जन्म के पूर्व की साठ पीढ़ियों तथा आगे आने वाली साठ पीढ़ियों को भवसागर से मुक्त कर देता है। संन्यासी के जो पैतृक दोष हैं तथा जो स्वयं के अपने शारीरिक दोष हैं, उन सभी को वह उसी तरह से भस्म कर देता है, जिस तरह तुषाग्नि सुवर्ण की गन्दगी को जला डालती है। हे सखा!

आप हमारी रक्षा करें, इस प्रकार कहकर दण्ड को धारण करना चाहिए। दण्ड उत्तम श्रेष्ठ बाँस का सीधा, छाल सहित, समान (संख्या युक्त) गाँठ वाला होना चाहिए।

क्रमशः ...

नरमपंथी दल के नेता के रूप में विख्यात थे गोपाल कृष्ण गोखले

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती प्रमुख नेताओं में से एक गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक बदलाव के अलावा सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रतिबद्ध थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें अपना गुरु माना था। गोखले के समय में कांग्रेस भारतीय राजनीति की मुख्यधारा को प्रकट करने वाली सर्वप्रमुख संस्था थी। वह कांग्रेस में नरमपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे और बातचीत की प्रक्रिया में भरोसा करते थे। उस समय के प्रमुख नेताओं का प्रयास था कि अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीयों को इज्जत मिलनी चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोपाल कृष्ण गोखले वैसे तो नरमपंथी दल के नेता के रूप में विख्यात थे लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के रूप में देश को सबसे बड़ा योगदान दिया था क्योंकि भारत को समझने की सीख गांधी को गोखले से ही मिली थी और राष्ट्रपिता ने उन्हें

अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ही वह शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पूरा देश घूमकर भारत को समझने की सलाह दी थी। गोखले की इस सलाह ने भारतीय आजादी के आंदोलन की एक नई दिशा तय कर दी। महात्मा गांधी गोखले के जबरदस्त प्रशंसक थे और उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकार किया था। गोखले उन नेताओं में थे जिनसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे।

महात्मा गांधी गोखले से काफी प्रभावित थे और यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वह जिन लोगों से प्रमुखता से मिले उनमें गोखले भी थे। गोखले के सुझाव को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने भारत की यात्रा की थी। इससे उन्हें भारत और आम भारतीय को समझने का मौका मिला। इसी क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से दो चार हुए। उनका मानना है कि गांधी के पहले कांग्रेस नेतृत्व एलीट किस्म का था जिसमें आम लोगों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन गांधी की लोकमुखी राजनीति से आम आदमी का उसमें प्रवेश हो गया और वह गांव-गांव तक पहुंच गई। इससे स्वतंत्रता आंदोलन में आम आदमी की सहभागिता और भूमिका बढ़ती गई। गोखले कालेज में शिक्षा हासिल करने वाली देश की शुरुआती पीढ़ियों में से एक के सदस्य थे। शिक्षा प्राप्त करने से उन्हें इसका महत्व समझ में आया और वह चाहते थे कि आम भारतीय भी शिक्षा के महत्व को समझें। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने इसके सार्वजनिक प्रसार के लिए काफी प्रयास किया।

अफगानिस्तान तक होगा चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट

गौतम मोरारका

पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद का उत्पादक, प्रश्रयदाता और प्रवक्ता माना जाता है। तालिबान को दुनिया में क्रूरता और महिलाओं पर निर्ममता बरतने के लिए जाना जाता है। चीन को विस्तारवादी नीतियों के चलते दुनिया में अशांति फैलाने और कोरोना जैसे वायरसों का आविष्कार और उसका प्रसार कर तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। इसलिए यह खबर काफी विरोधाभासी लगती है कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने पर सहमत हुए हैं। हम आपको बता दें कि इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में बैठक संपन्न हुई जिसमें कई बड़े निर्णय लिये गये। इन बड़े निर्णयों में सबसे बड़ा निर्णय यह है कि चीन अब अपनी बीआरआई परियोजना का अफगानिस्तान में भी विस्तार करेगा। इसके अलावा तीनों देश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शनिवार को इस्लामाबाद में आयोजित पांचवीं चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की वार्ता में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बयान में कहा गया है, ''तीनों पक्ष त्रिपक्षीय ढांचे के तहत राजनीतिक जुड़ाव, आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग और व्यापार, निवेश और संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने पर सहमत हुए।'' त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में हालांकि कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस बैठक के लिए अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष रूप से पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

इस बैठक में भाग लेने के लिए चीनी विदेश मंत्री छिन कांग गोवा में एससीओ की बैठक में भाग लेने के बाद सीधे वहां से इस्लामाबाद पहुँचे थे।

तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने शनिवार की त्रिपक्षीय बैठक के बाद रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी से मुलाकात की और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। शांति और सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समन्वय बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुत्तकी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से भी मुलाकात की और दोनों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।

इसके अलावा, पाकिस्तानी मीडिया में इस आशय की भी खबरें हैं कि इस त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान तालिबान चीन और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है। दरअसल तालिबान भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है इसलिए उसे उम्मीद है कि अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे में आने वाला चीनी निवेश उसकी दिक्कतें दूर कर देगा इसलिए चीन और पाकिस्तान की योजना को हरी झंडी दे दी गयी है। इसके तहत अफगानिस्तान के शासक तालिबान के हाथों अरबों डॉलर का निवेश लग गया है। हम आपको बता दें कि चीन अपनी बीआरआई परियोजना को पाकिस्तान से आगे ईरान और तुर्की तक ले जाना चाहता है।

बताया जा रहा है कि इस त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और 60 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया। इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जो संयुक्त बयान जारी किया है उसमें भी कहा गया है कि दोनों पक्ष अफगान लोगों के लिए अपनी मानवीय और आर्थिक सहायता जारी रखने और अफगानिस्तान में सीपीईसी के विस्तार पर सहमत हुए हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन और पाकिस्तान ने एक दशक पहले शुरू हुई परियोजना बीआरआई के तहत बनाये जा रहे सीपीईसी प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

हम आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान की विदेशों में संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। पाकिस्तान और चीन बार-बार यह मांग दोहरा रहे हैं कि अफगानिस्तान की संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाये। अब तक तालिबान शासन को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है लेकिन पाकिस्तान और चीन ने लगातार तालिबान शासन से संवाद बनाये रखा है और उसे करोड़ों डॉलर की मदद भी मुहैया कराई है। हालांकि पाकिस्तान के संबंध तालिबान शासन से पिछले वर्ष काफी बिगड़ गये थे लेकिन इन संबंधों में सुधार लाने के लिए चीन ने काफी प्रयास किये हैं क्योंकि अफगानिस्तान के लिए उसका अपना जो लक्ष्य है वह बिना पाकिस्तान की मदद के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन भी पाकिस्तान में ही किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक जून 2021 में चीन में हुई थी जिसके कुछ सप्ताह बाद ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था।

जहां तक अफगानिस्तान संबंधी भारत की रणनीति की बात है तो आपको बता दें कि भारत भी अपने इस पड़ोसी देश की हर तरह से मदद जारी रखे है। साथ ही भारत ने इस महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस द्वारा दोहा में बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया था। इस बैठक में विभिन्न देशों के विशेष दूतों ने भाग लिया था। इस बैठक का उद्देश्य तालिबान के साथ संवाद को लेकर एक आम समझ विकसित करना था। बैठक में चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, नॉर्वे, पाकिस्तान, कतर, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, यूरोपीय संघ और इस्लामी सहयोग संगठनों ने भाग लिया था।

बापू की दिनचर्या

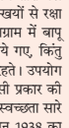

शौच

प्रात:कालीन प्रार्थना के बाद बापू प्राय: डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार कुछ देर सो जाते। कभी-कभी डाक वगैरह का काम निबटाते। सेवाग्राम में जब से रहने लगे, तभी से जरूरत पड़ने पर प्रार्थना के बाद वे पत्र लिखते- लिखाते और लेख लिखते। बाद में अक्सर कुछ देर सोकर थकान दूर कर होते। आगा खां महल में सुबह वे प्रार्थना के बाद दो चम्मच शहद और नींबू का रस आठ औंस गरम पानी में लेते। दिल्ली में अंतिम दिनों में भी प्रार्थना के बाद वे गरम पानी में शहद और नींबू का रस लेते। उन्हीं दिनों बिहार- यात्रा में प्रार्थना के बाद वे गरम पानी में केवल शहद लेते। अपने जीवन के अंतिम दिन प्रार्थना के पश्चात् वे कांग्रेस का संविधान प्रस्तुत कर रहे थे। पीने पाँच बजे उन्होंने गरम पानी में शहद और नींबू का रस लिया। बापू सुबह छह बजे शौच जाते। दिन भर में वे सामान्यत: चार बार शौच जाते। कुछ दिन शुरू-शुरू में वे शौच के लिए खेत में गए, लेकिन बाद में हमेशा कमोड या कमोड की तरह के पाखाने का उपयोग करते। अफ्रीका में आश्रम गृह के समीप लगभग डेढ़ फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। उसमें सारा मल डालकर मिट्टी से पाट दिया जाता। इससे दुर्गंध और मक्खियों से रक्षा होने के साथ ही अमूल्य खाद की प्राप्ति हो जाती। सेवाग्राम में बापू का तथा अन्य शौचालय इसी प्रकार के नए ढंग से बनाये गए, किंतु ग्रामविभाग के उपयोग के थे और वे बिलकुल स्वच्छ रहते। उपयोग के पश्चात् उन पर हर बार मिट्टी डाली जाती, जिससे किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती। बापू का आग्रह था कि शौचालय की स्वच्छता सारे घर की तुलना में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। संभवत: सन् 1938 का प्रसंग है। बापू कमोड पर शौच जाना छोड़कर नालीवाले आम शौचालय में जाने लगे थे। नियम यह था कि हर व्यक्ति शौच से निवृत होकर अपने मल पर थोड़ी मिट्टी डाल दे। एक दिन अमृतपाल नागावटीजी ने बापू को छोटे फावड़े से मिट्टी कुरेदते देखा तो वे तुरंत बापू के पास पहुंचे और बोले-लाइए बापू मैं डाल दूं मिट्टी। बापू बोले-अपने शौच पर तो मैं मिट्टी डाल चुका हूँ। यह मिट्टी तो मैं अपने बाद आनेवालों के लिए जमा कर रहा हूँ। अपने बाद आनेवालों की इतनी चिंता रहती थी बापू को। बापू शौचालय को पुस्तकालय- जैसा स्वच्छ रखने के लिए कहते, जहाँ बैठकर कुछ अध्ययन किया जा सके।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

महिला ब्लाक अध्यक्ष ने गृह मंत्री से की मुलाकात

रिसाली। श्रीमती हेमिन चतुर्वेदी दूसरी बार महिला ब्लाक कांग्रेस कमेटी 6 (नगर पॉलिक निगम रिसाली) की अध्यक्ष बनी है जिन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात करके उनका आभार प्रगट किया है.इस अवसर पर प्रमुख रूप से रिसाली निगम की महापौर श्रीमतीं शशि अशोक सिन्हा, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, श्रीमतीं प्रतिभा पाल,शेष जांगड़े सहित अन्य महिलाये उपस्थित थी।

ट्रक का पंवर बना रहे चालक व कंडक्टर को ठेका अज्ञात ट्रक ने

पिथौरा। सोमवार की सुबह नेशनल हाईवे 53 पर भगत देवरी के पास ट्रक का पंचर टायर बदलते चालक एवं कंडक्टर को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया और दोनों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक ओडिशा एवं एक बिहार का रहने वाला है। सोमवार की अलसुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में भगत देवरी के समीप एक ट्रक पंचर हो गई थी। सड़क किनारे खड़ी ट्रक का टायर ट्रक चालक एवं कंडक्टर मिलकर बदल रहे थे। इस बीच 5 से 6 बजे के बीच किसी अज्ञात ट्रक ने टायर बदल रहे दोनों पर ट्रक चढ़ा दी। उक्त घटना में ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि एक मृतक का हाथ कट कर दूर जा गिरा। घटना में दो लोगों की जान जाते देख आरोपी ट्रक चालक घटना स्थल से फरार हो गया। सुबह राहगीरों ने घटना की सूचना 112 की मदद से सांकरा पुलिस को दी।

वाणिज्य स्नातक सहायक शिक्षकों को गणित विषय पर प्रमोशन देने की माँग तेज

कांकेर। एक बार फिर से प्रदेश के वाणिज्य स्नातक सहायक शिक्षकों ने पूरे जोर-शोर से अपनी बरसों पुरानी माँग गणित विषय के विकल्प के तौर पर प्रमोशन देने की माँग दोहराई। इसी तारतम्य में राजधानी रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सभा में प्रदेश के वाणिज्य स्नातक सहायक शिक्षकों ने शिरकत कर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुचाई। सभा को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव शेख इमरान उल्लाह ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में गणित विषय के शिक्षकों की भारी कमी है। विशेषकर आदिवासी बाहुल्य बस्तर एवं सरगुजा संभाग में तो स्थिति बेहत गम्भीर है। जिसका सीधा असर इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य में हो रहा है। गणित विषय के शिक्षक नहीं होने से बच्चों को आगे की पढ़ाई और कैरियर निर्माण में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विकराल समस्या का एक मात्र हल है कि वाणिज्य विषय के स्नातक सहायक शिक्षकों को विकल्प के तौर पर गणित विषय पर प्रमोशन देकर प्रदेश के बच्चों के भविष्य को सवारा जा सकता है।

पद्मश्री उषा बारले का सम्मान हुआ

दुर्ग। दुर्ग तहसील सतनामी समाज के तत्वधान में दुर्ग के सतनामी आश्रम में अंतरराष्ट्रीय पंडवानी गायिका पद्मश्री डॉक्टर उषा बाई बारले का सम्मान किया गया .इस अवसर पर प्रमुख रूप से दुर्ग सतनामी आश्रम के अध्यक्ष एवं संरक्षक चंद्रशेखर बंजारे अमर दास बारले दुर्ग तहसील सतनामी समाज के अध्यक्ष दिनेश देशलहरे उपाध्यक्ष श्रीमती बसंती गायकवाड जनक सोनवानी महेंद्र बंजारे सचिव मोगरा डहरे नंहु महिपाल संदीप बंजारे जयेंद्र डहरिया कोषाध्यक्ष ओम कुमार खुटियारे मीडिया प्रभारी देव महंगे कार्यकारिणी सदस्य ऋषि टंडन गौकरण मांडले शीतल कोठारी शिव कुमार डहरे सितम बंजारे जुगल प्रसाद जोशी नागेश टंडन श्रीमती नीलू देशलहरे उपस्थित थे।

उतई में एल्डरमैन का पद रिक्त

दुर्ग। नगर पंचायत उतई मे एक साल बाद भी एक एल्डर्मैन का पद रिक्त है.बताया जाता है की एक साल पहले अचानक एल्डर्मैन चन्द्रहास वर्मा के निधन के बाद यह पद रिक्त हो गया है। एक नाम का चयन करके प्रभारी मंत्री के पास भेजे जाने की सूचना बार बार आती है। लेकिन इस रिक्त पद पर किस कांग्रेस नेता कार्यकर्ता की नियुक्ति होगी।जिसको लेकर असमन्श बरकरार है.इस एक रिक्त एल्डरमेन के पद हेतु दर्जन भर कांग्रिस नेता व कार्यकर्ता लालायित है। लेकिन नियुक्ति कब होगी।जिसको लेकर सिर्फ चर्चा हो रही है।अब तो छह माह बाद विधानसभा का चुनाव होना है।इससे पहले नियुक्ति की बात भीतर भीतर ही हो रही है।

प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग

दुर्ग। जिले के जेवरा-सिरसा थाना क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री में आज सुबह लगी आग से लाखों रूपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को 10 से 15 राउंड लगाना पड़ गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आज सुबह-सुबह सूचना मिली कि जेवरा-सिरसा क्षेत्र में संचालित एनके इंडस्ट्रीज में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची दमकल टीम के साथ पुलिस ने मोर्चा संभला। इस दौरान फैक्ट्री में चारों ओर आग फैल चुकी थी। दमकल कर्मियों ने लगातार मशक्कत करते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कई राउंड के बाद जब आग कुछ कम हुई तो फोन टेंडर के सहारे बची आग को बुझाया गया। बताया जाता है कि आग इतनी भीषण थी कि दमकल की गाड़ियों को यहां 10 से 15 राउंड लगाना पड़ गया। दूसरी ओर फैक्ट्री संचालक के अनुसार इस आगजनी में उसका लाखों का नुकसान हो गया है। पुलिस को संचालक ने बताया है कि उसकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के साथ ही पैक्ड प्रोडक्ट इस आगजनी में जलकर नष्ट हो गया है, जिसकी कीमत लाखों रूपए में है।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन

लोरमी के ग्राम खुड़िया में मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी 13 करोड़ 71 लाख 54 हजार की सौगात

लोरमी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज 8 मई को लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान ग्राम खुड़िया में 13 करोड़ 71 लाख 54 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जिसमें 1 करोड़ 20 लाख 33 हजार रूपए के 02 कार्यों का लोकार्पण और 12 करोड़ 51 लाख 21 हजार रूपए के 19 कार्यों का भूमिपूजन किया ।

जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ उनमें 2 करोड़ 79 लाख 05 हजार रूपए की लागत से ग्राम डिंडौरी से नवागांव दयाली मार्ग लम्बाई 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रूपए की लागत से जिले में संचालित अनुसूचित जाति-जनजाति, छात्रावास-आश्रमों में अनुरक्षण-जीर्णोद्धार, लघु निर्माण रंगाई-पुताई (गोबर पेंट) के कुल 24 कार्य, 78.74 लाख रूपए की लागत से ग्राम बिजराकापाखुर्द से कुदुरताल मार्ग लम्बाई 5.05 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 76.06 लाख रूपए की लागत से टी 2 से पथर्री लम्बाई 5 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 75 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमपुर का निर्माण कार्य, 66.53 लाख रूपए की लागत से ग्राम बघर्रा से कोदवामहंत लम्बाई 4.32 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 64.15 लाख रूपए की लागत से एल 087 से भूतकछार 4.23 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 60.86 लाख रूपए की लागत से एल 069 अमलीडीह से कोईलारी 3.05 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 58.12 लाख रूपए की लागत से टी 9 से बुधवारा 3.06 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 54.76 लाख रूपए की लागत से ग्राम कोदवामहंत से कोसाबाड़ी 2.947 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 46.92 लाख रूपए की लागत से एल 029 खेकतरा से नथेलापारा 2.37 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 44.36 लाख रूपए की लागत से ग्राम कुदुरताल से पथरताल 2.34 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 37.00 लाख रूपए की लागत से अग्रसेन वार्ड लोरमी में शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य, 33.45 लाख रूपए की लागत से रंगियापारा से परदेशीकापा 2.005 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 29.60 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में हमर लैब निर्माण कार्य, 29.30 लाख रूपए की लागत से एल 087 से करूहानार 1.71 किलोमीटर का निर्माण कार्य, 26.60 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी में ब्लड बैंक निर्माण कार्य, 16.36 लाख रूपए की लागत से ग्राम डिण्डौरी में शासकीय आयुर्वेद औषधालय निर्माण कार्य और 16.36 लाख रूपए की लागत से ग्राम कोदवामहंत में शासकीय आयुर्वेद औषधालय निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह 92.60 लाख रूपए की लागत से शासकीय राजीव गांधी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और 27.73 लाख रूपए की लागत से ग्राम अखरार में उपस्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया।

घर में भोजन ग्रहण करने पहुंचे मुख्यमंत्री को देखकर सरपंच और परिवारजन हुए गदगद

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम खुड़िया की सरपंच श्रीमती लक्ष्मीन बाई रामु निषाद के यहां भोजन किया। मुख्यमंत्री को किसान के घर पारंपरिक छत्तीसगढ़िया भोजन और व्यंजन परोसा गया। कांसे की थाली में परोसे गए भोजन में रोटी, दाल, चांवल, मशरूम , खट्टे दही में बनी जिमि कांदा , आलू गोभी बैगन, चेंच भाजी, चुनचुनिया भाजी, गलका, आम की चटनी, सलाद, आचार, पापड़ और अंत में खीर मुख्यमंत्री ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री को खीर का स्वाद खूब भाया और सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर परिवार के सदस्यों को भेंट भी दिया। साथ ही सबके साथ रुप फोटो भी कराई।

मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश

प्रदेश कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ सभी जिलों के थानों में दर्ज कराई एफआईआर

रायपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं उनके परिवारजनों की हत्या की साजिश के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस क्रम में कर्नाटक के चित्तुर से भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौर और भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला के थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस से की गई शिकायत में हत्या के षड्यंत्र रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है। कर्नाटक में भाजपा की करारी हार स्पष्ट नजर आ रही है।

कर्नाटक की जनता भाजपा की 40ब कमीशन लेने वाली सरकार से त्रस्त है मोदी और शाह का जुमला भी कर्नाटक की जनता समझ चुकी है। हवा हवाई बातें करने वाले और कर्नाटक को लूटने वाली भाजपा को अब अपनी विदाई नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा अब कांग्रेस नेताओं एवं के पार परिवार जनों की हत्या की साजिश रच रही है। साजिश कर्ताओं को भाजपा के बड़े नेताओं का समर्थन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों पर भरोसा कर रही है पूरा देश देखा है कि 1991 के चुनाव के दौरान किस प्रकार से चुनाव प्रचार के समय राजीव गांधी की हत्या की गई थी। अब भाजपा के विधायक प्रत्याशी मणिकांत राठौर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे एवं उनके परिवारजनों की हत्या की साजिश रच रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में साढ़े 12 हजार पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य में शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सीधी भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 06 मई, 2023 से आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 06 जून 2023 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 हजार 489 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक, 432 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती की जाएगी। व्यापमं भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा।

शैक्षणिक योग्यता- छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के मुताबिक अलग-अलग है।

सहायक शिक्षक- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड/बीएड/डीईआई ईडी, टीईटी पेपर I पास होना अनिवार्य है।

शिक्षक- संबंधित विषयों और कुल मिलाकर कम से कम 45ब अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीएड/बीएड/डीईआई ईडी,डिग्री। टीईटी पेपर II उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

लेक्चरर- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण। बी.एड होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु-सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एसटी/एसी वर्ग के लिए 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की गई है।

ऐसे करें आवेदन -सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाएं। होमपेज पर सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती लिंक पर क्लिक करें। खुद को रजिस्टर करें और आवेदन पत्र भरें। अपने दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें

सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया - भर्ती जारी... 12 हजार 489 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। 6,285 सहायक शिक्षकों, 5,772 शिक्षकों और 432 व्याख्याताओं के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 06 मई से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, व्यापमं से ली जाएगी परीक्षा। नियुक्ति आदेश जल संसाधन विभाग में 352 सब-इंजीनियरों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं।

भाजपा मतलब भ्रष्टाचार : भूपेश

रायपुर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान है इस बीच सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ते ही जा रही है। वहीं, आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जो कि कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचारक रहे हैं,ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव में सुपड़ा साफ होने की बात कही है। बघेल ने कहा है कि भाजपा मतलब भ्रष्टाचार। सीएम भूपेश बघेल ने दो अखबार की कटिंग ट्वीट करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक से भी भ्रष्ट भाजपा जा रही है। जैसे छत्तीसगढ़ की जनता ने अवैध कारनामों की सरगना भ्रष्ट भाजपा को विदा किया था, वैसे ही कर्नाटक से भी भ्रष्ट भाजपा जा रही है। भाजपा मतलब

भ्रष्टाचार! इससे पहले कल यानि रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के आरोपों पर करारा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि उनसे ज्यादा लालची आदमी कोई है ही नहीं, उन्हें पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने दी है। बिना रीढ़ का आदमी एक जांच क्या बैठी कि भाजपा की गोद में जा बैठे। उनकी नैतिकता क्या है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाएं। बता दें कि इससे पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि कर्नाटक में राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा सोनिया गांधी पिछले 20 साल से अकेले राहुल गांधी को खड़ा करने की लड़ाई लड़ रही हैं, अब यह व्यक्ति (राहुल गांधी) कैसे आकर कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे सकता है?

भत्ता योजना की जटिलता में उलझे बेरोजगार

कोरबा। जिला पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत 76 हजार बेरोजगारों में 3,262 युवाओं ने 2,500 रूपये बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किया है। भत्ता पाने के लिए जो गाइडलाइन दिए गए हैं वह बेहद जटिल है। इसकी वजह से युवा रूचि नहीं दिखा रहे। अभी 2,227 आवेदनों का सत्यापन हुआ है, जिसमें 837 आवेदन निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अभाव में हाल ही में पंजीयन कराने वालों ने भी आवेदन कर दिया है।

राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। गाइडलाइन जारी करने के बावजूद अपात्र बेरोजगार भी आनलाइन आवेदन कर रहे हैं। जिन कारणों से आवेदन निरस्त हो रहे हैं उनमें बिना नवीनीकरण के पंजीयन, हाल में कराए गया गया नया पंजीयन के साथ आवेदन करना है। प्राप्त हो रहे आवेदनों को जिले के सभी ब्लाक में सेक्टर बनाकर आनलाइन आवेदन करने वाले बेरोजगारों के दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में सेक्टर प्रभारियों के स्वीकृति मिलने के बाद ही योजना का लाभ मिलना है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आनलाइन आवेदन करने पर दस्तावेजों में किसी तरह की खामियां होने पर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

जारी गाइड लाइन के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से एक वर्ष के अंदर ही बना हो। इस तरह के कायदों को पूरा करने आवेदक असमर्थ हैं। इस वजह से भी आवेदन निरस्त हो रहे हैं। महीनेभर में करीब तीन हजार बेरोजगारों ने ही आनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 2.227 बेरोजगारों ने ही सत्यापन कराया है। जबकि 100 बेरोजगार तय तिथि पर सत्यापन कराने नहीं पहुंचे। इन्हें दोबारा मौका दिया गया है और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है।

आकाशीय बिजली गिरने से 20 झुलसे, तीन की हालत गंभीर

बीजापुर। बासागुड़ा क्षेत्र के गांव पोलमपल्ली में गाज गिरने से एक 22 साल के युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि सात महिला और दो बच्चों सहित 20 ग्रामीण झुलस गये जिनमें से तीन ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिनका बीजापुर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना रविवार शाम 6 बजे के लगभग की है।

मिली जानकारी अनुसार रविवार शाम 6 बजे के लगभग बासागुड़ा क्षेत्र से लगे गांव पोलमपल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और बादल भी जमकर गरजे। इसी वक्त तेंदूपत्ता फड़ में पत्ता बेचने पहुंचे ग्रामीणों को आकाशीय बिजली ने अपने चपेट में ले लिया। फड़ में मौजूद ग्रामीणों के समीप आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं 20 अन्य ग्रामीण झुलस गये। इनमें से तीन की स्थिति गंभीर बताई गई है। सभी पीड़ित बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आकाशीय बिजली के चपेट में आने से झुलसे लोगों में सात महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल हैं। बासागुड़ा थाना से लगभग 15 किमी दूरी पर है। गांव के लोगों ने अपने निजी वाहन से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया है। बासागुड़ा से एंबुलेंस भी प्रभावितों की मदद के लिए भेजी गई थी। पुलिस थाना प्रभारी व जवानों के सहयोग से ग्रामीणों को राहत दी जा रही है। डा तरुण गोटा ने बताया कि सभी घायल ग्रामीणों को अस्पताल तक लाने में लगभग 10 बजे गये।

ईडी अफसर दफ्तर में बुलाकर मारपीट कर रहे : बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। उन्होंने ईडी अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। कहा कि, ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुलाकर मारपीट कर रहे हैं। यह बात वह लगातार कहते आ रहे हैं। धमकी दी जा रही है। परिजनों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की बात कही जा रही है। पहले से लिखे नोट पर जबरदस्ती और डराकर साइन कराए जा रहे हैं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सब मिथ्या हैं।

रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि, महिलाओं से भी रात-रात भर नियम विरुद्ध ईडी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। खाना नहीं दे रहे हैं। खाना देते हैं तो पीने के लिए पानी नहीं देते। सोने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से प्रताड़ित कर जबरिया हस्ताक्षर करा लिया गया है। जो नोट है, वह पहले से लिखकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के करने के

लिए कहा जाता है। नहीं करने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। परिवार को प्रताड़ित कर फर्जी केस में फंसाए जाने की धमकी दी जाती है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, कोयला घोटाले में पांच हजार करोड़ बोले, लेकिन तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद बता नहीं पाए। अब दो हजार करोड़ का बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चल- अचल संपत्ति जब्त नहीं की गई है। अगर की है, तो बताया ही नहीं गया कि कितनी की गई। तीन साल से आईटी और ईडी लगी हुई है। जो आरोप लग रहे हैं, वो पूरी तरह से मिथ्या है। ये निंदनीय है।

भ्रष्टाचारियों के सिर पर गदा मारेंगे बजरंगबली

कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, वहां पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंगबली भ्रष्टाचारियों के सिर पर गदा जरूर मारेंगे। असम के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी बार-बार निष्ठा साबित करनी पड़ रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के बाद वह सोनिया गांधी पर लगातार हमले कर रहे हैं ताकि अपने बीजेपी के नेताओं को खुश कर सकें।

ईडी का आबकारी राजस्व में कमी के आरोप पूरी तरह मिथ्या और मनगढंत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने के छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के आबकारी घोटाले के आरोपों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आबकारी राजस्व में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में आबकारी राजस्व में कमी के आरोप पूरी तरह मिथ्या, और मनगढंत हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि केन्द्र की एजेंसियां भाजपा के राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रही है। बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में नई आबकारी नीति आई थी। तब से अब तक नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। न तो आधकारी बदले गए, और न ही प्लेसमेंट एजेंसियां, और डिस्टलरी आदि में बदलाव किया गया है। सीएम ने आगे कहा कि भाजपा शासनकाल में वर्ष-2017 में आबकारी राजस्व करीब 4 हजार करोड़ मिला था। अब बढ़कर 6 हजार करोड़ हो गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी राजस्व में डेढ़ गुनी बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में ईडी का आबकारी राजस्व में कमी का आरोप मिथ्या, और मनगढ़ंत है।

शराब घोटाले समेत सभी घोटाले की त्वरित सुनवाई हो - भाजपा

प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा

रायपुर। आज भाजपा कार्यालय, एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव , नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल , रायपुर संभाग प्रभारी, विधायक सौरभ सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी की बड़ी कारवाई के बाद उसके द्वारा जारी प्रेस रिलीज से भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप फिर साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता को बुरी तरह लूट-खसोट कर भूपेश बघेल सरकार 10 जनपथ का खजाना भर रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला तो देश भर में इस तरह का सबसे बड़ा घोटाला है। यह केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा और उससे भी अधिक संगीन है।

अरुण साव ने कहा कि अभी तक शराब घोटाले के अलावा, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, तबादला घोटाला समेत प्रदेश के हर तरह के संसाधनों की लूट मचा कर कांग्रेस की यह बेईमान सरकार फिरंगियों और मुगलों से भी अधिक बेदर्द तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा है। इसने घोटालों की श्रृंखला में मनमोहन सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। इस घोटाले में मुखिया के निर्देश पर अनवर ढेबर द्वारा एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का निर्माण किया गया जिस के अंतर्गत भ्रष्टाचार का पैसा पार्ट,, पार्ट क्ष एवं पार्ट ष्ट के अंतर्गत किया। ईडी के रिलीज में साफ कहा गया है कि ये लोग घोटाले की रकम के अंतिम लाभार्थी नहीं है। अपना कमीशन काट कर ये लोग शेष रकम को पॉलिटिकल मास्टर% को भेज देते थे। क्या यह बताने की जरूरत है कि ये पॉलिटिकल मास्टर% कौन है? सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल मास्टर% ही इस सिंडिकेट का सरगना है।

अरुण साव ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसी कच्ची और देसी शराब प्रदेश भर के 800 दुकानों में खपाये गये हैं, जिसे वैध तरीके से भी बेचा नहीं जा सकता है। इस शराब से शासकीय खजाने को तो अरबों का चूना लगा ही, प्रदेशवासियों की जान का भी सौदा किया गया। आरोप के अनुसार फैक्ट्री में शराब बना कर उसे सीधे दुकानों को बेचा जा रहा था और यह रकम सीधे राजनीतिक खज़ान में जमा होता था। जहरीली शराब से हुई मौतों को भी भूपेश सरकार ने शराब बेचने का बहाना बना दिया। शराब की कीमत 50 से 80रु बढ़ाने, बड़ी संख्या में कच्ची और अन्य अवैध शराब से मौत होने के बावजूद शासन शराब राजस्व में कमी दिखाता रहा और अपनी पीठ भी थपथपाता रहा था। जबकि सच्चाई यह थी कि शराब का अधिकांश पैसा सीधे पॉलिटिकल सरगना हड़प जाता था। यही कारण है कि ईडी की कारवाई होते ही अचानक शराब राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

इस मामले में सबसे दुखद पक्ष है एक सहज और भोले आदिवासी मंत्री को इस्तेमाल किया जाना। श्री कवासी लखमा इस विभाग के मंत्री इसीलिए बनाए गए ताकि वे भूपेश बघेल और एजाज के इस सिंडिकेट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकें। इसी तरह ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में भी अध्यक्ष का पद इसलिए ही खाली रखा गया ताकि लूट की रकम का शेयर और किसी को नहीं देना पड़े।

छत्तीसगढ़ बदलने के नारे के साथ आयी इस सरकार ने पूरी सरकार को 'अंडरवर्ल्ड' के रूप में बदल दिया था। और इस तमाम घोटाले का असली लाभार्थी, असली मास्टरमाइंड और 'पॉलीटिकल मास्टर' कौन था, इसके बारे में अब कोई भी संदेह नहीं रह गया है। नकली होलोग्राम लगाकर घटिया शराब अधिक दाम में बेची गई, इससे 1200 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई।

ईडी का आबकारी राजस्व में कमी के आरोप पूरी तरह मिथ्या और मनगढंत - बघेल

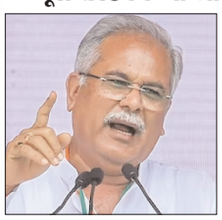

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने के छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ के आबकारी घोटाले के आरोपों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आबकारी राजस्व में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में आबकारी राजस्व में कमी के आरोप पूरी तरह मिथ्या, और मनगढंत हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि केन्द्र की एजेंसियां भाजपा के राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रही है।

श्री बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में नई आबकारी नीति आई थी। तब से अब तक नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। न तो अधिकारी बदले गए, और न ही प्लेसमेंट एजेंसियां, और डिस्टलरी आदि में बदलाव किया गया है। सीएम ने आगे कहा कि भाजपा शासनकाल में वर्ष-2017 में आबकारी राजस्व करीब 4 हजार करोड़ मिला था। अब बढ़कर 6 हजार करोड़ हो गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी राजस्व में डेढ़ गुनी बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में ईडी का आबकारी राजस्व में कमी का आरोप मिथ्या, और मनगढ़ंत है। सीएम ने कहा महालेखाकार ने भी जांच की थी, और आबकारी विभाग को क्लीनचिट दी गई। उन्होंने कहा कि दो साल पहले फरवरी में आबकारी कारोबार से जुड़े लोगों के यहां आईटी ने छापे मारे थे। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट प्रेस नोट तक जारी नहीं की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मार्च को ईडी ने फिर से छापेमारी की। तब भी प्रेस नोट जारी नहीं किए गए। शर्म के मारे वो नहीं बता पाई कि किसकी, कितनी चल- अचल संपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के अफसर यहां के लोगों से मारपीट कर रहे हैं। महिलाओं को खाने-पीने नहीं दिया गया। जबकि हस्ताक्षर लिए गए। उन्होंने कहा कि कोयला में 5 सौ करोड़, और आबकारी में दो हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक किसी की चल-अचल संपत्ति को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। सीएम ने कहा कि ईडी के सारे आरोप मिथ्या हैं। केन्द्र की एजेंसी भाजपा के राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रही है।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

भगवान के दर पर भेदभाव!

हमारे देश में राजनेता या और भी दूसरे लोग समता की बात तो खूब करते हैं लेकिन व्यवहार में वह समता कहीं नजर नहीं आती कम से कम जो अधिक लोकप्रिय मंदिर हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती। चाहे वह बाबा विश्वनाथ की काशी हो या उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर। पिछले दिनों मैंने एक बुजुर्ग महिला का वीडियो देखा जिसमें उसे बाबा के दर्शन को लेकर नंबर इंतजार करना पड़ा, तो वह पीतल वाले बेरिकेड्स लांघती है.. वहाँ उपस्थित तमाम लोगों से तीखी बहस करती है... और अंततः महाकालेश्वर पर जल चढाती है। वह महिला थी, बुजुर्ग थी इसलिए वह ऐसा कर सकी। बाकी कोई दूसरा होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता। उसे जबरन बाहर कर दिया जाता। प्रश्न यह है कि ऐसी नौबत क्यों आती है? ऐसा इसलिए होता है कि आम लोग घंटो लाइन लगे रहते हैं और तथाकथित वीआईपी महाकाल के दर्शन करने आते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ गर्भगृह के दर्शन करा दिया जाता है। तब लोगों को गुस्सा आता है। उस दौरान लोग मूक दर्शक बनकर खड़े-खड़े एक तरह से वीआईपी-तमाशा देखते रहते हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था का कुछ बंधन बना कर रखा गया है। मंत्री,अफसर अपने पद का लाभ उठा कर आम लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। प्रोटोकॉल के लिहाज से कभी-कभार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री तक तो यह व्यवस्था कुछ-कुछ स्वीकार हो सकती है, लेकिन पता लगा कलेक्टर साहब को सपरिवार दर्शन कराने है, तो सारे श्रद्धालुओं को एक-दो घंटे के लिए रोक दिया जाता है । आखिरी हम यह कैसा समाज विकसित कर रहे हैं, जहां जनसेवा के लिए तैनात अफसरों को इतना महत्व दिया जाता है ? अफसर जनता का नौकर ही है न! मगर हमारे सिस्टम ने नौकर को इस देश में राजा बना दिया है । यह नकली किस्म का लोकतंत्र बहुत दुखद है । देश में सच्चा लोकतंत्र तो उसी दिन आएगा, जब किसी भी मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार में कलेक्टर भी खड़ा दिखाई दे.. पुलिस का बड़ा अधिकारी भी खड़ा नज़र आए.. मंत्री भी खड़ा रहे। कभी-कभी मुख्यमंत्री भी खड़ा हो जाए कतार में। वह तो बहुत ही महानतम दिन होगा, जब हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी कतार में खड़े देखेंगे। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कम -से-कम अभी व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं है । लेकिन फिलहाल इतना तो करें कि कम-से-कम कलेक्टरों, अफसरों और मंत्रियों के लिए श्रद्धाओं को रोकने की व्यवस्था खत्म हो। पिछले दिनों उज्जैन में यह नजारा देखने को मिला। काशी की तरह उज्जैन में भी भव्य कारीडोर बन बन गया है। उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है तो वहां भी अब शीघ्र दर्शन के लिए शुल्क भी लिया जाने लगा है। भस्म आरती और गर्भगृह के दर्शन के लिए 750 रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है। जिसे निःशुल्क दर्शन करना है, तो उसके लिए (गोया बड़ी कृपा की गई) उसे 150 फीट दूर से कांच के पार से बाबा के दर्शन करने होंगे, जहां से वे ठीक से नजर भी नहीं आते। मुझे लगता है, ऐसा सहज सरल सिस्टम बनना चाहिए, जिसके चलते श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो। सर्वाधिक तकलीफ तो लोगों को उस वक्त होती है, जब भगवान के द्वार किसी वीआईपी के लिए खोल दिया जाते हैं और लोकतंत्र के राजा को यानी लोक को अर्थात लोगों को रोक दिया जाता है। यह कैसा इंसाफ है? इस पर विचार की जरूरत है। भगवान के दर पर तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहां भी अगर भेदभाव दिखाई दे तो काहे का धर्मस्थल? धर्म स्थलों में भेदभाव अधर्म से कम नहीं।

स्वयंसेवकों ने मनाया देवर्षि नारद जयंती

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरानी बस्ती नगर के स्वयंसेवकों ने राम मंदिर शाखा टिल्लू चौंक में देवर्षि नारद जयंती मनाया। इस कार्यक्रम में नगर के ज्येष्-श्रेष्ठ स्वयंसेवक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत प्रचार प्रमुख कनिराम ने देवर्षि नारद जी के बारे में बताया कि कैसे वे देवताओं के अलावा दैत्यों के साथ भी उनका मधुर संबंध था। उन्हें आद्य पत्रकार भी कहा जाता है। कनिराम ने बताया कि विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी के प्रणेता एकनाथ रानाडे ने कैसे बिना सरकारी मदद भारत के आम जनता से सहयोग लेकर विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण कराया।

महिला मोर्चा ने पूरे छत्तीसगढ़ में किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन

■ शराबबंदी का वादा करने वालों ने किया 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा ने आज कांग्रेस सरकार में 2 हजार करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में पूरे प्रदेश में संभाग मुख्यालयों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय दुर्ग संभाग में, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह ने रायपुर ग्रामीण में व बस्तर संभाग में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

विधानसभा के पास रायपुर ग्रामीण जिला के प्रदर्शन में शामिल रायपुर संभाग प्रभारी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि जब तक ईडी की छापेमारी नहीं हुई थी तब तक शराब बिक्री की बड़ी रकम इस रैकेट के पास जा रही थी। जब से ईडी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है तब से आबकारी राजस्व में आश्चर्यजनक रूप से आय बढ़ गई। साफ है कि जो पैसा गलत हाथों में जा रहा था, वह ईडी के डर से सरकारी खजाने में जाने लगा। लेकिन 4 साल में भूपेश बघेल सरकार में 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला किया गया।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने शराब घोटाले का मामला विधानसभा में पूरे तथ्यों के साथ उठाया था लेकिन सरकार जब इस घोटालेबाजी की संरक्षक हो तो इस पर रोक कैसे लग सकती थी। सरकार ने आबकारी घोटाले की पारदर्शी जांच कराना तो दूर की बात है, घोटाले को दबाने की पूरी कोशिश की लेकिन ईडी ने मिस्टर 40 परसेंट की पोल खोल दी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा ईडी के बीच आर्गनाइज्ड पालिटिकल सिंडिकेट बना है - कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव आज एक बार फिर से ईडी के प्रवक्ता के रूप में सामने आये वे ईडी के तथा कथित आरोपो की सच्चाई के लिये कसमें खा रहे थे। इसके पहले भी जब ईडी की कार्यवाही हुई थी तब भी ईडी ने अपना अधिकृत प्रेसनोट जारी नहीं किया उसके पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रेस नोट जारी करके ईडी की कार्यवाही का ब्योरा सामने रखा उसके तीन दिन बाद ईडी ने रमन सिंह के प्रेस नोट की हूबहू नकल कर प्रेसनोट जारी किया था। इन दोनो प्रकरणों से साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में ईडी भाजपा के राजनैतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रही है। भाजपा और ईडी के बीच में आर्गनाइज्ड पालिटिकल सिंडीकेट बना हुआ है। ईडी ने कुछ एक व्यापारियों, अधिकारियों से पूछताछ करके तथा कथित रूप से यह घोषणा कर दिया कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। अरूण साव ने दावा किया है कि ईडी ने शराब दुकानों में सीधे शराब बिकवाने का खुलासा किया है। ईडी का दावा है शराब के बोटलो में नकली होलोग्राम लगाये गये अवैध शराब बेची गयी।

कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

रायपुर। जन चौपाल में आज कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आम नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनसे आवेदन प्राप्त किए। जन चौपाल में आज लगभग 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर डॉ भुरे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बी.बी पंचभाई, रायपुर एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जन चौपाल में आज ग्राम पंचायत कूरां के बुद्धेश्वर देवांगर ने पैतृक कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने, ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच ने कुम्हारी भाठापारा में बोर एवं हैण्डपंप स्वीकृत करने, ग्राम पंचायत बरतोरी की सरपंच ने जमीन आबंटन दिलाने, रायपुर की नया तालाब गुढ़ियारी निवासी सुमन साहू ने विधवा पेंशन बनवाने, बीरगांव निवासी इकराम अहमद ने निर्मित अवैध कब्जा हटवाने, जवाहर नगर निवासी देव आनन्द साहू ने दिव्यांग पेंशन दिलवाने, कुशालपुर निवासी मुन्ना ठाकुर ने मलसाय तालाब में मुण्डन कार्यक्रम के लिए चबूतरा, प्रशाधन निर्माण और पूजन सामाग्री विसर्जन हेतु कुण्ड निर्माण कराने, आरंग तहसील के ग्राम पाहंदा के पोषण रामजी ने त्रुटि सुधार करने, मंदिरहसौद निवासी नीरा बाई पटेल ने रिकार्ड दुरूस्त करवाने और ग्राम टेकारी निवासी के.पी. टंडन ने भूमाफियाओं द्वारा काबिज निर्मित मकान पर बलपूर्वक अवैध रूप से अतिक्रमण कर लेने की शिकायत पर आवेदन दिया।

'द केरल स्टोरी' को छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स फ्री करे-सरोज पांडे

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की सांसद (राज्यसभा) डॉ. सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग की है। डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि द केरला स्टोरी वास्तव में छत्तीसगढ़ की भी स्टोरी है, यह देशभर की स्टोरी है। भाजपा सांसद डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि द केरला स्टोरी भारतीय समाज की सभी बेटियों को जागरूक करने, उन्हें लव जिहाद जैसी साजिशों से सावधान करने और उन्हें आतंकवाद का टूल्स बना देने की साजिश के विरुद्ध भी जागरूक करेगी। सुश्री पांडेय ने छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की चल रही चर्चाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि कांग्रेस सामाजिक सद्भावना को नष्ट करने वाली आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 'द केरला स्टोरी% आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों का पर्दाफाश करने वाली फिल्म है। भाजपा सांसद डॉ. (सुश्री) पांडेय ने कहा कि देश की कांग्रेस सरकार यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ की बेटियों की भला चाह रही है तो द केरला स्टोरी को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित नहीं, बल्कि टैक्स फ्री करने की घोषणा करे। डॉ. (सुश्री) पांडेय ने सवाल किया कि जब-जब आतंकवाद के खिलाफ समाज को जागरुक करने की कोशिश होती है।

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड

रायपुर। उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ के ''प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन'' को देश की प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। विभाग को यह अवार्ड देश के कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता करते हुए कई चरणों की प्रस्तुतिकरण, वोटिंग एवं उपलब्धियों के कारण प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नैक के द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदण्डों के अनुरूप शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अकादमिक स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर नैक से संबद्धता प्राप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया है। कुल 211 अर्हता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में से 197 शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराकर छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि कॉलेज में प्रवेश लेने वालों छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां 2018-19 में करीब 2 लाख 26 हजार 373 छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश लिया वहीं यह संख्या वर्ष 2022-23 में 48 प्रतिशत बढ़कर 3 लाख 35 हजार 139 हो गई है। जो कि 2018-19 की तुलना में एक लाख 8 हजार 766 अधिक है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विगत 4 वर्षों में कुल 33 नवीन शासकीय एवं 76 अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

रेडक्रॉस का उद्देश्य मानवता की सेवा - राज्यपाल

रायपुर। राजभवन में आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत सक्रिय रूप से कार्य करने वाले नि-क्षय मित्रों एवं जिलों के जिलाधीशों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। साथ ही रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिचंदन ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बिना किसी भेद-भाव के सभी की सेवा करता है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिचंदन ने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की छत्तीसगढ़ इकाई, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है। रेडक्रॉस द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, आयोजित करने के साथ ही गरीब मरीजों को इलाज के लिए राशि, दिव्यांग मरीजों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किया जाता है। कोविड के दौरान रेडक्रॉस ने जो कार्य किया वह अतुलनीय है।

बैस जी पर उम्मीद की नजरें,क्या सक्रिय राजनीति में फिर वापसी होगी

रायपुर। राज्यपाल रमेश बैस जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं आखिर चर्चा क्यों छिड़ जाती है..? किसी समय छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की राजनीति में भाजपा के कद्दावर नेता रहे रमेश बैस लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे.केन्द्र में कई मर्तबे मंत्री रहे,लेकिन राज्य बनने के बाद उन्हे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पार्टी ने पसंद नहीं किया। अटल-आडवाणी का समय गुजरने के बाद जब मोदी-शाह का प्रभुत्व पार्टी में चला तो कुछ समय तक वे भी हाशिये में रखे गए। इस बीच जब पन्द्रह साल का भाजपा राज बुरी तरह ध्वस्त हुआ,और छत्तीसगढियावाद का

जोर दिखा तब पार्टी के भीतर रमेश बैस की तरफ उम्मीद के रूप में देखा जाने लगा था कि केन्द्र ने उन्हे राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी सौंपते हुए राज्य से बाहर कर दिया। वे झारखंड व त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। अब उन्हे औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र का अहम जिम्मा दिया गया है,ऐसे समय में जब शिव सेना का विभाजन हुआ और भाजपा पुनः सत्ता में लौटी। जबकि बात उनके गृहराज्य छत्तीसगढ़ की करें तो भाजपा साढ़े चार साल पहले जहां थी आज भी वहीं नजर आ रही है। दरअसल इतनी सारी बातें इसलिए आ रही है कि जब भी बैस छत्तीसगढ़ आते हैं एक राजनेता की तरह स्वागत,सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व आम लोगों का शिष्टाचार मेल जोल,उनकी सादगी व सरल व्यवहार की पहचान व शिष्टता है।

पारिवारिक व सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए इस बार भी वे प्रवास पर हैं तब मीडिया ने फिर से उन्हे कुरेदा लेकिन संवैधानिक पद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही उन्होने बात की,हां इतना जरूर कह गए कि पार्टी ने उन्हे बहुत कुछ दिया है,जो भी जिम्मेदारी पार्टी आगे तय करेगी वे करने तैयार हैं। एक खास बात यह भी कि उनके पारिवारिक व धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए राज्य भाजपा के अधिकांश लोग पहुंचे। चूंकि छह माह बाद विधानसभा का चुनाव है इसलिए फिर चर्चा छिड़ गई है कि क्या बैस जी की सक्रिय राजनीति में वापसी होगी,तब जबकि भूपेश बघेल के अक्खड़ छत्तीसगढियापन से भाजपा निपट नहीं पा रही है।

परसा कोयला ब्लॉक शुरू कराने ग्रामीणों ने पुनः लगायी गुहार

■ मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन देकर रखेंगे

अम्बिकापुर। उदयपुर विकासखण्ड में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को आवंटित परसा कोयला ब्लॉक को शुरू कराने के लिए प्रभावित ग्रामीणों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। परसा कोयला ब्लॉक के परिचालन के लिए आने वाले छह ग्राम साल्ही, जनार्दनपुर, हरिहरपुर, फतेहपुर, तारा, और घाटबर्रा ग्राम के 140 ग्रामीणों ने अपने हस्ताक्षरित ज्ञापन के द्वारा राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव । क्षेत्रीय विधायक से अनुरोध किया है।

इन ग्रामों से सात सदस्यीय दल आज

रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपेगे। इस दौरान फतेहपुर के समल सिंह पोर्ते व केश्वर सिंह पोर्ते, ग्राम साल्ही के मोहरलाल कुसरो व मनोज कुमार पोर्ते, ग्राम तारा के रंगीलाल मरकाम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया की हम सभी परसा कोल ब्लॉक से प्रभावित परिवार के सदस्य हैं। हमारी निजी भूमि का अधिग्रहण इस ब्लॉक के लिए दो वर्ष पूर्व हुआ था, और इसके लिए हमें मुआवजा भी मिल चुका है। लेकिन इस अधिग्रहण में पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के तहत हमने रोजगार प्राप्त करने का विकल्प चुना है। यही नहीं हमारी अधिग्रहित भूमि का नामांतरण भी आरआरवीयूएनएल को हो गया है, किन्तु आज तक खदान शुरू न हो पाने से हम अब तक बेरोजगार घूम रहे हैं। चूंकि कानूनी तौर पर हमारी जमीन पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है इसलिए इसमें हम कृषि कार्य भी नहीं कर पा रहें हैं और न ही कंपनी में हमें नौकरी मिल पा रही है। इससे हमें आर्थिक क्षति भी हो रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.